दैनिक जागरण

परिश्रम ही योग्यता को अर्जित करने का माध्यम है

लोकसभा का नया अध्यक्ष

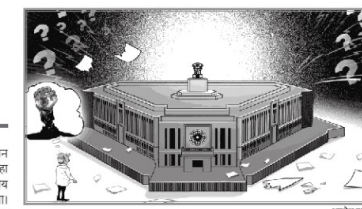

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का गठन होने के बाद अब प्रतीक्षा इसकी है कि नई लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा? इसे लेकर जहां भाजपा अपने सहयोगी दलों और विशेष रूप से तेलुगु देसम पार्टी एवं जनता दल-यू नेताओं के साथ विचार-विमर्श कर रही है, वहीं विपक्ष इस कोशिश में है कि लोकसभा उपाध्यक्ष का पद उसके हिस्से में आए। चूंकि इस बार उसका संख्याबल अधिक है, इसलिए वह लोकसभा उपाध्यक्ष पद पाने के लिए हरसंभव कोशिश कर रहा है। कुछ विपक्षी नेताओं ने यह भी कहा है कि यदि सत्तापक्ष लोकसभा उपाध्यक्ष पद विपक्ष को देने के लिए तैयार नहीं होता तो उसकी ओर से अध्यक्ष पद के लिए भी अपना उम्मीदवार खड़ा किया जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो ऐसा पहली बार होगा, जब इस पद के लिए चुनाव होगा। विपक्षी दलों के नेता तेलुगु देसम पार्टी और जनता दल-यू को यह नसीहत भी देने में लगे हुए हैं कि लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उनमें से किसी को अपनी दावेदारी पेश करनी चाहिए। यह ठीक है कि गठबंधन सरकारों में यह पद घटक दलों के हिस्से में जाता रहा है, लेकिन मौजूदा सरकार वैसी गठबंधन सरकार नहीं, जैसी वाजपेयी अथवा मनमोहन सिंह सरकार थी। इन गठबंधन सरकारों के मुकाबले वर्तमान सरकार की स्थिति इसलिए अलग है, क्योंकि भाजपा बहुमत से पीछे रहने के बाद भी संख्याबल में मजबूत है।

फिलहाल इसके आसार कम हैं कि जनता दल-यू अथवा तेलुगु देसम पार्टी की ओर से लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए आग्रह किया जाएगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वाजपेयी सरकार के समय अध्यक्ष पद तेलुगु देसम पार्टी के पास ही था। वाजपेयी सरकार एक वोट से इसीलिए गिरी थी, क्योंकि तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष ने ओडिशा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके कांग्रेस सांसद गिरधर गोमांग को इस आधार पर सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे दी थी कि उन्होंने लोकसभा की सदस्यता नहीं छोड़ी थी। लोकसभा अध्यक्ष केवल सदन की कार्यवाही ही संचालित नहीं करता, बल्कि कुछ मौकों पर मत विभाजन के समय निर्णायक भूमिका भी निभाता है। सदस्यों को उनके कदाचरण के लिए दंडित करने और दलबदल की स्थिति में उन्हें अयोग्य ठहराने का फैसला भी वही करता है। सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होने के कारण इस पद की महत्ता बढ़ जाती है। उचित यह होगा कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष पद को लेकर पक्ष-प्रतिपक्ष में कोई सहमति कायम हो। सदन के सुचारु रूप से संचालन के लिए यह आवश्यक है। इससे भी आवश्यक यह है कि जो भी अध्यक्ष बने, वह दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करे। उसे निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए, बल्कि दिखना भी चाहिए। ध्यान रहे कि जब-जब ऐसा नहीं होता, तभी सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच विवाद पैदा होते हैं।

नए पर्यटन स्थल

मैदानों में गर्मी बढ़ने से हिमाचल प्रदेश के पर्यटन उद्योग को गति मिली है। राज्य के लगभग सभी पर्यटन स्थलों में होटल पूरी तरह पैक हैं। इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े लोग उत्साहित हैं। उधर पर्याप्त व्यवस्थाएं न होने से पर्यटकों को समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पर्यटन स्थलों में अधिक वाहन आने से पर्यटकों को पार्किंग की समस्या से जूझना पड़ रहा है। कई स्थानों पर सड़कों पर घंटों जाम लग रहा है। राज्य में अधिक पर्यटकों का आना सुखद है, लेकिन पर्याप्त सुविधाएं न होना हर किसी को अखर रहा है। यातायात नियंत्रित करने में पुलिस कर्मचारियों की कमी महसूस की जा रही है। राज्य में नए पर्यटन स्थनों को विकसित करने की भी आवश्यकता है। नए पर्यटन स्थल विकसित न होने के कारण पर्यटक प्रमुख पर्यटन स्थलों का ही रुख कर रहे हैं। नए पर्यटन स्थल विकसित होने से सिर्फ संबंधित क्षेत्र का ही विकास नहीं होगा बल्कि प्रमुख पर्यटन स्थलों से भी भार कम होगा। सरकार को इस संबंध में गंभीरता से प्रयास करने चाहिए। इस बीच देखा गया है कि पर्यटन स्थलों के साथ मुख्य सड़कों के किनारे गंदगी के अलावा प्लास्टिक कचरे के ढेर लग रहे हैं। लोग इधर-उधर कचरा फेंक रहे हैं। इसे कतई उचित नहीं ठहराया जा सकता है। यह समझना आवश्यक है कि यदि कोई स्थल किसी को अच्छा लगता है तो उसे गंदा नहीं किया जाना चाहिए। प्रशासन को भी चाहिए कि मुख्य सड़कों के किनारे कूड़ेदान लगवाए जाएं। अन्य राज्यों से आने वाले लोग नदी-नालों के किनारे न जाएं और प्रशासन की ओर से दिए दिशानिर्देश का पालन करें। स्थानीय लोगों और पर्यटकों को आपसी सौहार्द बनाए रखना चाहिए ताकि किसी तरह के विवाद में न फंसें।

पर्यटकों की सुविधा के लिए प्रदेश में नए पर्यटन स्थल विकसित करना समय की मांग है

राष्ट्रीय हितों पर बने सहमति

विवेक काटजू

अगर दुनिया को राष्ट्रीय सुरक्षा पर संसद में असहमति और कटुता देखने को मिली तो यह देश के लिए घातक होगा

प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी का तीसरा कार्यकाल आरंभ हो गया है। अपने सुदीर्घ राजनीतिक जीवन में मोदी पहली बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। हालांकि सरकार पर सहयोगी दलों के दबाव की अटकलों के बीच मंत्रिपरिषद गठन और विभागों के आवंटन के माध्यम से उन्होंने यही संदेश दिया कि उनकी शैली नहीं बदली है और कमान पूरी तरह उनके हाथ में रहेगी। उन्होंने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति से संबंधित महत्वपूर्ण मंत्रालयों में कोई फेरबदल नहीं किया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रमुख सचिव जैसी अहम नियुक्तियों में भी पुराने लोगों को ही मौका दिया। इस बीच उन्होंने गठबंधन का भी बार-बार उल्लेख किया। यह संदेश उन्हें समय-समय पर दोहराते रहना होगा।

शपथ ग्रहण के कुछ दिन बाद ही पीएम मोदी जी-7 से जुड़े आयोजन में शामिल होने के लिए इटली गए। तीसरे कार्यकाल में यह उनका पहला विदेशी दौरा रहा। उनके इस दौरे की उपयोगिता को लेकर कुछ लोगों के मन में कोई संदेह रहा हो तो वह अनावश्यक कहा जाएगा। अतीत में तो बेहद कमजोर गठबंधन की सरकारों के मुखिया भी वैश्विक मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। वास्तव में 1989 से 2014 तक 25 वर्षों के दौरान देश में गठबंधन सरकारों का ही दौर रहा और यही वह अवधि थी जब भारतीय अर्थव्यवस्था का कायाकल्प आरंभ हुआ। उस प्रक्रिया ने भी भारत के वैश्विक कद को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाई। इस लिहाज से जी-7 सम्मेलन में मोदी की उपस्थिति एक सराहनीय कदम रहा। चूंकि इसमें विश्व के सबसे शक्तिशाली देशों की सहभागिता होती है और इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्यसागरीय क्षेत्र जैसे मुद्दे भी भारतीय हितों की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे, इसलिए सम्मेलन में भारत की भागीदारी पूरी तरह समझ आती है।

एक राजनयिक के रूप मेरा अनुभव यही कहता है कि अंतरराष्ट्रीय बिरादरी को इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई सरकार किसी एक दल के बहुमत से चल रही है अथवा गठबंधन सहयोगियों के भरोसे। असल में सरकार का राजनीतिक स्थायित्व और उसका नेतृत्व करने वाले नेता का महत्व उससे कहीं ज्यादा होता है। अगर उन्हें इन पहलुओं को लेकर संशय रहता है तो वे सरकार के साथ सक्रियता में संकोच करते हैं। इटली में मोदी ने जिन नेताओं से मुलाकात की, वे इससे अवगत होंगे कि पूर्व की तरह इस बार मोदी की पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और विपक्षी दलों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया। हालांकि मोदी के साथ संवाद में उनकी भाव-भंगिमा ने यही दर्शाया कि उन्हें मोदी के नेतृत्व और उनकी सरकार की स्थिरता को लेकर संदेह नहीं। इन नेताओं और दूसरे अन्य देशों की नजर इस पर जरूर होगी कि चूंकि मोदी पहली बार किसी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं तो क्या वे अपनी आर्थिक एवं विदेश नीति के मोर्चे पर किसी प्रकार के संशोधन-समायोजन करेंगे। वैश्विक नेताओं ने इटली में मोदी के साथ अपनी बैठकों में शायद परोक्ष रूप से इस सवाल के जवाब की टोह लेने का प्रयास भी किया होगा। वे मोदी सरकार के अगले बजट को भी गहनता से परखेंगे कि उनकी सरकार अब कौनसी राह पकड़ने वाली है। ऐसा इसलिए, क्योंकि भारत की नीतियां और बाजार इन देशों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।

अवधेश राजपूत

समकालीन विश्व में भारत की स्थिति को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर न भी पेश किया जाए, तो भी यह निश्चित है कि अतीत की तुलना में वैश्विक मोर्चे पर भारत कहीं अधिक मजबूत है। बीते दो दशकों में देश ने तेज प्रगति की है और उसकी रफ्तार मोदी सरकार के दौरान भी बरकरार रही। संभव है कि विकास का पूरा प्रभाव कतार में खड़े अंतिम लोगों तक अभी अपेक्षित रूप से न पहुंच पाया हो, लेकिन इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ है। भारत को विकास के नए क्षितिज तक पहुंचाने के लिए अभी भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। यदि इन क्षेत्रों को लेकर राजनीतिक सहमति का भाव निर्मित होता है तो देश की राह आसान होगी, लेकिन ऐसा होना कुछ मुश्किल लग रहा है। आवश्यक यही है कि हमारा राजनीतिक वर्ग ऐसी किसी सहमति पर पहुंचे कि देश के समक्ष कायम प्रमुख रणनीतिक चुनौतियों से कैसे निपटा जाए। भारत का इतिहास साक्षी है कि जब भी राजनीतिक वर्ग विभाजित हुआ, तब देश सामरिक चुनौतियों से निपटने में अक्षम रहा।

आज देश के समक्ष सबसे प्रमुख रणनीतिक चुनौती चीन से जुड़ी है। उसने अप्रैल-मई, 2020 से ही लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर आक्रामक रुख-रवैया अपनाया हुआ है। बीते चार वर्षों से सैन्य, राजनयिक और राजनीतिक स्तर पर कई दौर की वार्ताओं के बावजूद मुद्दों का प्रभावी समाधान नहीं निकल पाया है। तिब्बत में भी चीन अपनी सैन्य ताकत और बुनियादी ढांचा बढ़ा रहा है। भारत के पड़ोस में भी चीन आक्रामकता दिखाने पर तुला है। विगत चार वर्षों के दौरान मोदी सरकार ने चीनी दुस्साहस का हरसंभव तरीके से जवाब देने का प्रयास किया है। चूंकि नई संसद में विपक्ष की तादाद बढ़ी है तो संभव है कि सुरक्षा एवं वैदेशिक मामलों पर अब पहले की तुलना में सरकार से अधिक जवाब-तलब होता दिखे। जम्मू-कश्मीर में नए सिरे से सिर उठाते पाकिस्तानी आतंकवाद से निपटने का मुद्दा भी इसमें शामिल होगा। अगर चीन, पाकिस्तान और पूरी दुनिया को हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सार्वजनिक विमर्श से लेकर संसद में असहमति और कटुता देखने को मिली तो यह देश के लिए बहुत घातक होगा।

राष्ट्रीय हितों का यही तकाजा है कि न केवल राजग सहयोगियों, बल्कि विपक्षी दलों से भी निरंतर संवाद जारी रहे। इसका उद्देश्य मुख्य मुद्दों पर सहमति बनाने का होना चाहिए। अगर इनपर एका होती है तो देश के दुश्मनों से निपटने में सरकार की शक्ति में वृद्धि होगी। आवश्यक नहीं कि ऐसे सभी संवादों को सार्वजनिक ही किया जाए। इसे नेताओं के भरोसेमंद विशेषज्ञों के जरिये पर्दे के पीछे से भी शुरू किया जा सकता है। इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए और विपक्ष उस पर जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े।

(लेखक विदेश मंत्रालय में सचिव रहे हैं)

response@jagran.com

भाजपा को बाहर से ज्यादा अंदर से खतरा

राजीव सचान

नई परिस्थितियों में भाजपा को सबसे अधिक जोर अपनी कार्यप्रणाली को सुधारने पर देना होगा

यह तो तय है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव में अपने अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन के कारणों की समीक्षा करनी शुरू कर दी होगी, लेकिन यह कहना कठिन है कि वह इन कारणों की तह तक जाकर उनका निवारण भी कर सकेगी, क्योंकि ऐसा तब संभव हो पाता है, जब गलतियों को स्वीकार करने के साथ ही उनके लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह बनाने का काम किया जाता है। फिलहाल भाजपा के सामने चुनौती यह नहीं है कि मोदी सरकार के स्थायित्व को मजबूती कैसे दी जाए? उसके सामने बड़ी चुनौती आगामी विधानसभा चुनाव हैं। यदि भाजपा महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और फिर उसके बाद अन्य राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाती तो इससे एक तो जनता के बीच यह संदेश जाएगा कि उसका प्रभाव कम होता जा रहा है और दूसरे, उसके नेताओं एवं कार्यकर्ताओं का मनोबल भी और गिरेगा। ऐसे में विपक्ष को यही संदेश जाएगा कि आगामी आम चुनावों में भाजपा को सत्ता से बाहर किया जा सकता है। यह स्थिति बनेगी या नहीं, इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति में एक सप्ताह भी लंबा समय होता है।

इसकी चर्चा तो खूब हो गई कि भाजपा के कमजोर प्रदर्शन का एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश समेत कुछ और राज्यों में खराब प्रत्याशियों का चयन और विपक्ष की ओर से बनाए गए नैरेटिव की काट न कर पाना रहा, लेकिन इस पर भी चर्चा होनी चाहिए कि भाजपा के कार्यकर्ता उसके सबसे मजबूत समझे जाने वाले गढ़ उत्तर प्रदेश में भी हताश-निराश क्यों थे? पार्टी नेतृत्व के लिए इसकी तह तक जाना आवश्यक है, क्योंकि भाजपा एक कैडर आधारित दल है और ऐसे दलों के उत्थान-पतन में नेताओं-कार्यकर्ताओं के मनोबल की एक बड़ी भूमिका होती है। किसी दल के नेता-कार्यकर्ता तब निराश होते हैं, जब अपनी सरकार होते हुए भी उनकी सुनवाई नहीं होती और यहां तक कि उनके सही काम भी नहीं हो पाते। ऐसी स्थिति कई कारणों से बनती है और मूलतः तब बनती है, जब सरकार नौकरशाही पर कुछ ज्यादा ही निर्भर हो जाती है। नौकरशाही पर निर्भरता का दुष्परिणाम यह होता है कि विधायकों, सांसदों और यहां तक कि मंत्रियों को भी अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के जायज काम कराने में मुश्किल पेश आती है। जब नौकरशाहों को यह आभास हो जाता है कि उन्हें सत्तारूढ़ दल के प्रतिनिधियों को महत्व नहीं देना तो फिर वे विधायकों, सांसदों और मंत्रियों तक को भाव देना बंद कर देते हैं। इसके चलते इन जनप्रतिनिधियों के समर्थकों को भी यह पता चल जाता है कि नेताजी की तो अपनी ही सरकार में नहीं चलती और यहीं से उनकी निराशा और साथ ही सरकार एवं पार्टी नेतृत्व से मोहभंग का सिलसिला शुरू हो जाता है।

कमजोर प्रदर्शन ने बढ़ाईं चुनौतियां। फाइल

जब कोई सरकार नौकरशाही के भरोसे ज्यादा रहती है तो फिर नौकरशाह मनमानी करने लग जाते हैं। स्थिति तब और बिगड़ जाती है, जब इसकी कोई पूछ-परख नहीं होती कि कहीं नौकरशाही बेलगाम होकर मनमानी तो नहीं कर रही है? इसके चलते सरकार जमीनी हकीकत से कट जाती है। यदि पार्टी कार्यकर्ता जमीनी हकीकत के बारे में फीडबैक देना भी चाहें तो सरकार और संगठन में कोई फीडबैक लेने वाला नहीं होता। नरेन्द्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा के बारे में यह कोई नई-अनोखी बात नहीं कि संगठन में वही होता है, जो सरकार चाहती है। इसमें संदेह है कि टिकट वितरण में संगठन की कोई खास भूमिका रही होगी। नौकरशाही पर अधिक भरोसा भाजपा की अधिकांश सरकारों की एक पुरानी समस्या रही है। इस समस्या की चपेट में केंद्रीय सत्ता भी है। शासन संचालन नौकरशाहों के बिना नहीं हो सकता, लेकिन इसका भी कोई मतलब नहीं कि नौकरशाह तो सेवा विस्तार पा जाएं, सेवानिवृत्ति बाद महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो जाएं अथवा निकट संबंधियों को चुनाव लड़ाने में समर्थ हो जाएं, लेकिन पार्टी नेताओं-कार्यकर्ताओं की निगमों, आयोगों आदि में समय रहते नियुक्तियां न होने पाएं।

इस लोकसभा चुनाव में भाजपा से एक गलती यह भी हुई कि उसने सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिये जिन वर्गों को खुद से जोड़ा था, उनकी अधिक परवाह नहीं की और यह मानती रही कि वे पहले की तरह उसके साथ बने रहेंगे, लेकिन कई कारणों से ऐसा नहीं हुआ। सरकारी योजनाओं के जरिये लाभार्थी वर्ग के रूप में भाजपा का जो एक नया वोट बैंक तैयार हुआ था, उसमें सेंध लग गई और पार्टी का परंपरागत वोट बैंक भी उससे छिटक गया। किसी भी दल को यह मानकर नहीं चलना चाहिए कि जो मतदाता समूह उससे जुड़ गया है, वह उससे आगे भी जुड़ा रहेगा। इस मामले में तो मुस्लिम वोट बैंक भी किसी दल का सगा नहीं। बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल किशनगंज क्षेत्र से असदुद्दीन ओवैसी के पांच विधायक इसलिए जीत गए थे, क्योंकि वहां के मुसलमानों ने अपने लोगों को जिताना बेहतर समझा। इसी तरह 2009 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता सपा का साथ छोड़कर कांग्रेस के पाले में चले गए थे। इसके चलते कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से लोकसभा की 21 सीटें जीतने में सफल रही थी। तब मुस्लिम मतदाता सपा से इसलिए बिदक गया था, क्योंकि मुलायम सिंह ने भाजपा नेता कल्याण सिंह को अपने दल में शामिल कर लिया था। यह भी किसी से छिपा नहीं कि जब मायावती ने दलित-ब्राह्मण एका के तहत हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है.. का नारा दिया था तो ब्राह्मण मतदाता बसपा के साथ हो गए थे। कुल मिलाकर भाजपा को विपक्ष का मुकाबला करने के लिए अपनी कार्यशैली बदलनी होगी, जो सरकार के संचालन में भी दिखे और संगठन में भी।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

सत्य का मार्ग

सत्य का मार्ग गरिमापूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर चलने के लिए स्वाभिमान और आत्मसम्मान रूपी अनुचरों की आवश्यकता होती है। बिना इनके सहयोग के इस मार्ग पर एक पग भी नहीं बढ़ा जा सकता। सत्य की सामर्थ्य को चुनौती देने के लिए निरंतर परीक्षाएं होती हैं। इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के लिए जीवटता से डटे रहना आवश्यक है। सत्य का मार्ग कांटों से भरा हुआ भी है। बाधाएं यहां हर समय डेरा डालकर बैठे रहती हैं। इनसे अविचलित होकर जो आगे बढ़ता है, वही इतिहास रचता है। सत्य और धर्म का मार्ग एक दूसरे के पूरक हैं। जहां नीति है वहां धर्म है। वहीं सत्य भी है। सत्य धर्म का सारथी है। सत्य जहां चलता है धर्म स्वतः वहीं अपना मार्ग प्रशस्त कर लेता है।

सत्य सदैव हमें मर्यादा में रखता है। भगवान श्रीराम सदा सत्य के साथ थे। उनका जीवन कष्टकर रहा, परंतु उन्होंने सत्य, मर्यादा और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उन्होंने मानव मात्र के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि किस तरह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर नवपथ का निर्माण संभव है। फिर उस पथ का अनुगमन युगों-युगों तक आने वाली पीढ़ियां करती हैं।

वर्तमान में असत्य के वशीभूत होकर लोग भविष्य को कष्टदायी बना रहे हैं। तात्कालिक सुख के लिए असत्य, अधर्म और अनीति का पक्ष ले रहे हैं, किंतु स्मरण रहे कि असत्य थोड़े समय के लिए ही लाभ दे सकता है। असत्य के बल पर थोड़े समय के लिए ही सम्मान एवं सत्कार प्राप्त किया जा सकता है, परंतु जब असत्य की डोर टूटती है तब सब कुछ धराशायी हो जाता है। जिस प्रकार बड़ी मीनार के ध्वस्त होने पर चारों ओर धूल का गुबार दिखाई देता है कुछ ऐसा ही उसके बाद का दृश्य दिखाई देने लगता है। इसलिए हमें अपने जीवन में सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए। सत्य के साथ धर्म, मर्यादा और नीति जैसे दिव्य गुण स्वतः ही आपका वरण कर लेंगे।

ललित शौर्य

जीवाश्म ईंधन पर घटे निर्भरता

सुधीर कुमार

डोमिनिका ने समस्त बिजली आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का फैसला किया है

डोमिनिका गणराज्य जीवाश्म ईंधन का पूरी तरह उपयोग बंद करने वाला दुनिया का पहला देश बनने जा रहा है। अपनी नई ऊर्जा नीति के तहत डोमिनिका ने समस्त बिजली आवश्यकताओं को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा करने का फैसला किया है। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पर निर्भरता समाप्त करने का यह कदम डोमिनिका की पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस परिवर्तन के जरिये डोमिनिका न केवल अपनी कार्बन फुटप्रिंट को कम करेगा, बल्कि अपनी अर्थव्यवस्था को भी दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करेगा।

डोमिनिका ने 2050 तक शुद्ध-शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। हालांकि वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में अपेक्षाकृत कम योगदान के बावजूद डोमिनिका जलवायु परिवर्तन के प्रति एक संवेदनशील देश रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण डोमिनिका को बड़ी आर्थिक कीमत चुकानी पड़ रही है। जलवायु परिवर्तन संबंधी ठोस नीतियों के अभाव के कारण 2050 तक डोमिनिका को फसलों के पैदावार में 30 प्रतिशत में कमी, गरीबी में वृद्धि, पर्यटन में कमी, आपदाओं में वृद्धि और सकल घरेलू उत्पाद में कमी जैसे आर्थिक जोखिम उठाने पड़ सकते हैं। इसी कारण उसने भूतापीय और सौर ऊर्जा जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के सहारे ऊर्जा-आत्मनिर्भरता की पहल की है।

जीवाश्म ईंधन के दोहन से वातावरण में कार्बन डाईआक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों की मोटी परत जमा हो जाती है। इन गैसों द्वारा अवशोषित वायुमंडल की गर्मी ही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। जीवाश्म ईंधन न सिर्फ पर्यावरण क्षरण, बल्कि मानव स्वास्थ्य और समाज के लिए भी नुकसानदायक है। जीवाश्म ईंधन से दूरी और अक्षय ऊर्जा को बढ़ावा देना एक खुशहाल भविष्य के लिए आवश्यक है। अच्छी बात है कि भारत भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्र ने 2030 तक अपनी स्थापित बिजली का 40 प्रतिशत हिस्सा गैर-जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने का लक्ष्य घोषित किया है और उसी वर्ष तक कार्बन उत्सर्जन की तीव्रता को 45 प्रतिशत से कम करके 2005 के स्तर से नीचे करने में जुटा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अनुसार, 2030 तक भारत में सौर और पवन ऊर्जा की संयुक्त स्थापित क्षमता 51 प्रतिशत हो जाएगी, जो अभी 23 प्रतिशत है। जाहिर है स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्र में भारत एक आकर्षक बाजार में परिणत हो रहा है। बहरहाल दुनिया के सभी देशों को जीवाश्म ईंधनों पर अपनी निर्भरता को चरणबद्ध तरीके से घटाने का प्रयत्न करना चाहिए। अक्षय ऊर्जा जीवाश्म ईंधनों का सर्वोत्तम विकल्प है। ऊर्जा के ये स्रोत असमाप्य हैं और यह पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल भी है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

ईवीएम को बदनाम करने की मुहिम

'ईवीएम पर बेतुकी बातें' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में बिल्कुल सही कहा गया है कि बार-बार चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाकर उसे लांछित करना सही नहीं। जब निर्वाचन आयोग एक बार ईवीएम को हैक करने की चुनौती दे चुका है और जब कोई ऐसा कर पाने में सक्षम नहीं हो सका तो फिर तभी इस विवाद का पटाक्षेप हो जाना चाहिए था। रह-रहकर इस मशीन को बदनाम करना उचित नहीं। यह राजनीतिक दलों की अपरिपक्वता को ही दर्शाता है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को तो कम से कम इस मामले में परिपक्वता दिखानी चाहिए जिसके शासनकाल में ही ईवीएम से चुनाव कराने की व्यवस्था शुरू हुई थी। ईवीएम से हुए चुनाव के जरिये ही कांग्रेस कई साल केंद्र की सत्ता में रही। अब भी यदाकदा राज्यों में उसकी सरकार बन जाती है तब उसे ईवीएम में कोई खोट नहीं दिखाई देती, लेकिन हारने पर वह ईवीएम पर ठीकरा फोड़ने लगती है। अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती तो क्या राहुल गांधी दोनों सीटों से इतने भारी अंतर से चुनाव जीतने में सफल हो सकते थे। ऐसे तमाम सवाल हैं जो ईवीएम को लेकर विपक्षी दलों के अनर्गल प्रलाप और सुविधाजनक रवैये की पोल खोल सकते हैं। इसलिए अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए उन्हें ईवीएम पर सवाल उठाना बंद कर देना चाहिए और यदि कोई साक्ष्य हों तभी इस मामले में अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। यदि ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सुबूत होते तो वे अब तक सामने आ चुके होते।

रवि वार्ष्णेय, बुलंदशहर

मेलबाक्स

संदेह के घेरे में प्रतियोगी परीक्षाएं

'सरकार के सामने परीक्षा की घड़ी' शीर्षक से युक्त लेख में प्रेमपाल शर्मा ने एनटीए द्वारा आयोजित नीट परीक्षा पर जो सवाल खड़े किए हैं, वह न केवल गंभीर हैं अपितु प्रतियोगी परीक्षाओं को संदेह के घेरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब नीट जैसी अतिविशिष्ट प्रतियोगी परीक्षा संदेह के घेरे में आई है, इससे पहले भी उप्र और बिहार में आयोजित होने वाली पुलिस और प्राइमरी शिक्षक भर्ती की प्रतियोगी परीक्षाओं में सेंधमारी के चलते सरकार को परीक्षाएं रद करनी पड़ी थीं। प्रतियोगी परीक्षा में गड़बड़ी होने पर उसको रद कर देना आसान सी बात है, लेकिन इससे परीक्षार्थियों की मनोदशा पर जो विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसकी चिंता कौन करेगा? किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को फूलप्रूफ तरीके से संपन्न कराना सरकार के साथ परीक्षा आयोजित कराने वाली नियामक संस्था की महती जिम्मेदारी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से देखा जा रहा है कि कुछ संगठित गिरोह प्रतियोगी परीक्षा में सेंधमारी करने में कामयाब हो जाते हैं। ऐसा क्यों और कैसे होता है? इस पर केंद्र और राज्य सरकारों को गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में होने वाली सेंधमारी, पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं की वजह से न केवल सरकार की फजीहत होती है अपितु उसे प्रतियोगी छात्रों के आक्रोश का सामना भी करना पड़ता है।

डा. वीपी पांडेय, अलीगढ़

छात्र हितों की अनदेखी

आज हमारे शिक्षा तंत्र की नींव को पुनः परिभाषित करने की अति आवश्यकता है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट ने छात्रों के मनोबल को तोड़ा है और उनके सपनों को धूमिल किया है। हर साल लाखों छात्र इस परीक्षा की कठिनाइयों से जूझते हैं, परंतु कुछ ही को सफलता मिलती है। यह प्रतिस्पर्धा न केवल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालती है, बल्कि समाज में असमानता भी बढ़ाती है। समाज के हर तबके के छात्रों को समान अवसर मिलना चाहिए। सरकार को राज्य स्तरीय परीक्षाओं का आयोजन कर, छात्रों को अपने ही राज्य में शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। इससे छात्रों को अपने परिवार से दूर नहीं होना पड़ेगा और वे मानसिक तनाव से मुक्त रह सकेंगे। शिक्षा प्रणाली में व्यावहारिक ज्ञान और कौशल विकास को प्रोत्साहन देना चाहिए। रटने की प्रवृत्ति से दूर होकर, वास्तविक जीवन के अनुभवों पर आधारित शिक्षा को महत्व देना आवश्यक है।

अमरजीत कुमार, औरंगाबाद, बिहार

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। बुधवार, 19 जून 2024

फिर न आए ये नौबत

मेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए होने वाली परीक्षा NEET में इस साल हुई कथित गड़बड़ियों का मामला दिनोदिन गंभीर होता जा रहा है। NTA का ढुलमुल, आधा-अधूरा और अपारदर्शी रवैया मामले को संभालने में कोई मदद नहीं कर रहा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फटकार लगाते हुए NTA से ठीक ही कहा कि अगर 0.001% भी लापरवाही हुई है तो उससे सख्ती से निपटना होगा।

पेपरलीक के आरोप | अफसोस की बात यह है कि NTA न केवल परीक्षा संचालित करने का फूलप्रूफ इंतजाम नहीं कर सकी बल्कि सामने आ रही शिकायतों और आरोपों पर भी गंभीर रुख नहीं दिखा सकी। पेपरलीक की शिकायतें शुरू में ही सामने आ गई थीं। मगर उनकी सही ढंग से जांच कराने के बजाय उसने अपनी ताकत उनका खंडन करने में लगाई। नतीजा यह कि गुजरात, बिहार और हरियाणा जैसे राज्यों में पुलिस द्वारा की जाने वाली गिरफ्तारियां NTA के दावों पर सवाल बनकर खड़ी हो गई हैं।

NTA: सुप्रीम कोर्ट की फटकार

ग्रेस मार्क्स का मसला | शक का सबसे बड़ा कारण यह है कि NTA ने अपनी तरफ से पारदर्शिता नहीं रखी। स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स देने के फैसले पर तो सवाल हैं ही, उसे देने के तरीकों को लेकर भी कई तरह के संदेह जताए जाते रहे हैं। इन संदेहों पर कोई संतोषजनक जवाब देने के बजाय NTA ने एक और कमिटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए इन ग्रेस मार्क्स को रद्द कर दिया और उन स्टूडेंट्स के लिए फिर से परीक्षा लेने की घोषणा कर दी।

राजनीतिक मुद्दा | सवालों और संदेहों को सीधे संबोधित करने के बजाय उनसे बचने की जो यह प्रवृत्ति दिख रही है, उससे इन आरोपों को बल मिलता है कि दाल में कुछ काला है। यह भी एक वजह है कि NEET में कथित गड़बड़ियों का मसला राजनीतिक रूप ले चुका है। कांग्रेस नेता इसे मुद्दा बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी इसे लेकर सड़क पर उतर चुकी है।

शोरगुल में न दबे | ऐसे में इस बात का ध्यान रखना और जरूरी हो जाता है कि शोरगुल में मूल मसला दब न जाए। भूलना नहीं चाहिए कि NEET में हुई इन कथित गड़बड़ियों से न केवल इस बार इसका हिस्सा बने 24 लाख स्टूडेंट्स की आशा-निराशा जुड़ी है बल्कि देश में मेडिकल को करियर बनाने का सपना देख रहे लड़के-लड़कियों का विश्वास भी जुड़ा है। भावी डॉक्टरों की प्रामाणिकता तो NEET और NTA की विश्वसनीयता पर निर्भर करती ही है। इसलिए जो हुआ है, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए, दोषियों को उपयुक्त सजा मिले और भविष्य में ऐसी बदइंतजामी न हो, इसके ठोस इंतजाम किए जाएं।

इन दिनों

अधूरी ख्वाहिश

मृत्युंजय राय

कुछ दिनों इस बात पर खूब हल्ला मचा कि चीन के सेंट्रल बैंक के गोल्ड खरीदने की वजह से बेशकीमती धातु की कीमत रेकॉर्ड लेवल तक पहुंच गई। बात सही है। चाइनीज सेंट्रल बैंक ने पिछले कुछ समय में अमेरिकी असेट्स में निवेश घटाया और गोल्ड में बढ़ाया है। चीन, भारत सहित कुछ अन्य देशों में भी यह ट्रेंड देखा गया। इसके बाद कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का दबदबा तोड़ने के लिए ब्रिक्स के मार्फत चीन एक योजना को अंजाम दे रहा है, गोल्ड की खरीदारी उसी का हिस्सा है। लेकिन चीन की करंसी युआन की असल स्थिति क्या है? चाइनीज सेंट्रल बैंक के गवर्नर पी गोन्गशेंग ने हाल ही में कहा था, 'ग्लोबल पेमेंट्स में युआन दुनिया की चौथी मोस्ट एक्टिव करंसी बन गया है। ट्रेड फाइनैंस में यह तीसरे नंबर पर है।' सेंट्रल बैंक का यह भी दावा है कि चीन दूसरी दुनिया के साथ जो कारोबार करता है, उसमें से आधे का सेटलमेंट युआन में हो रहा है।

फिर भी युआन की ग्लोबल पोजिशन चीन की आशा के मुताबिक नहीं है। 2008-09 के ग्लोबल फाइनैंशल क्राइसिस के वक्त कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में युआन का दबदबा बढ़ेगा। 2008 में गोल्डमैन सैक्स ने कहा था कि 2020 तक दुनिया के विदेशी मुद्रा भंडार में युआन की हिस्सेदारी 15-20% हो जाएगी। लेकिन पिछले कई वर्षों से डॉलर की तुलना में युआन की ताकत नहीं बढ़ रही है। 2014 में यह अमेरिकी करंसी के मुकाबले पीक वैल्यू पर पहुंची थी। तब से युआन में 16% से अधिक की गिरावट आ चुकी है। लेकिन 2016 में इसे IMF की इस्तेमाल किए जाने वाली रिजर्व करंसी में शामिल किया गया। इसके बावजूद दूसरे देशों के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल किए जाने को लेकर युआन को बहुत कामयाबी नहीं मिली। पिछले साल तक इसकी हिस्सेदारी 2.3% ही थी।

कई जानकारों को लग रहा है कि ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में टकराव बढ़ सकता है। इसे ध्यान में रखकर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देश सप्लाई चेन में अपनी चीन पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो चीन भी पश्चिम के प्रतिबंधों से खुद को बचाने के उपायों पर काम कर रहा है। ढाई साल पहले जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो पश्चिमी देशों में रखा उसका विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज कर दिया गया। चीन के ध्यान में यह बात है। इसलिए उसने एक बार फिर युआन का अंतरराष्ट्रीय दायरा बढ़ाने की कोशिश तेज कर दी है। लेकिन अभी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का हिस्सा 60 फीसदी है। इसमें हाल-फिलहाल कमी की सूरत भी नहीं दिख रही, इसलिए चीन को युआन का अंतरराष्ट्रीय दर्जा बढ़ाने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ेगा।

एकदा

उस्तादों के उस्ताद

महान शायर मिर्जा गालिब ने मीर तकी मीर के बारे में अगर यह कहा था कि *'रेख्ते के तुम्हीं उस्ताद नहीं हो गालिब/कहते हैं अगले जमाने में कोई मीर भी था'*, तो यूं ही नहीं कहा था। उर्दू यानी रेख्ता भारत में जन्मी, यहीं पली-बढ़ी, तो उसकी नींव में एक बड़ा हिस्सा मीर का भी है। उर्दू को लेकर मीर काफी सेंसेटिव थे। भाषा सही रास्ते चले, इसके लिए अच्छे-अच्छे लोगों से वह दुश्मनी मोल ले लिया करते। उस दौर में दिल्ली में एक साहब थे मीर कमरुद्दीन मिन्नत। बड़े आदमी थे। परंपराओं के ज्ञाता होने के कारण बादशाह के दरबार में भी बैठा करते। उन्हें रेख्ता में शेर कहने का शौक तो था, पर वो शायरी के शुरुआती दौर में थे। एक दिन मिन्नत साहब ने उर्दू में एक गजल कही, मगर शब्दों से मुतमईन न हुए। गजल को वो मीर तकी मीर के पास ले गए, गरज यह कि उसमें मौजूद गलतियां सुधरवा लें। मीर ने गजल देखी और सिर झटकते हुए उनसे पूछा, 'आपका वतन कहां है?' कमरुद्दीन ने जवाब दिया, 'हुजूर, सोनीपत, पानीपत मेरा वतन है।' मीर साहब ने बड़े प्यार से कहा, 'सैयद साहब, उर्दू-ए-मुअल्ला, खास दिल्ली की जबान है। यह आपके बस की नहीं। बेहतर हो कि आप इसमें तकलीफ ना कीजिए। हां, अपनी फारसी-वारसी में ही कह लिया कीजिए। उर्दू-ए-मुअल्ला को बख्श दीजिए।' यह सुनते ही वो नाराज हो गए और बादशाह से शिकायत करने की ठानी। मीर को पता चला तो उन्होंने बड़ी बेपरवाही से एक शेर कहा, *'रेख्ता रुत्बे को पहुंचाया हुआ उस का है/मो'तकिद (कायल मानने वाला) कौन नहीं 'मीर' की उस्तादी का।'*

Subrata Dhar

संकलन : **जमील गुलरेज**

हाल में कुछ बातों के जरिये यह दिखाने की कोशिश हुई कि BJP और संघ में दूरी बढ़ी है

RSS चीफ की बात का क्या है मतलब

अरुण आनंद

हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जिनके कारण कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या लोकसभा चुनावों के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) में मतभेद पैदा हो गए हैं। ऐसा भी अनुमान लगाया गया कि संघ शायद BJP और नरेंद्र मोदी सरकार की कार्यशैली से खुश नहीं है।

अटकलों का कारण | इन अनुमानों के पीछे दो प्रमुख घटनाएं थीं। पहला, BJP को लेकर एक आलोचनात्मक लेख एक अंग्रेजी साप्ताहिक में छपना, जिसे संघ का मुखपत्र बताया गया। दूसरा, सरसंघचालक मोहन भागवत का नागपुर में दिया गया एक भाषण, जिसमें उन्होंने चुनावों को लेकर कुछ बातें कहीं। ऐसा लगता है कि संघ की कार्यशैली को लेकर आधी-अधूरी जानकारी होने के कारण और भ्रम पैदा करने के लिए सुनियोजित ढंग से ऐसा विमर्श बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि संघ और BJP में टकराव की स्थिति है। आइए तथ्यों पर नजर डालते हैं।

संघ का कोई मुखपत्र नहीं | पहले उस साप्ताहिक के आलेख की बात कर लेते हैं। इस संदर्भ में दो तथ्य महत्वपूर्ण हैं। पहला, यह साप्ताहिक संघ का मुखपत्र नहीं है। संघ कई बार कह चुका है कि उसका कोई मुखपत्र नहीं है। संघ के समविचारी कई प्रकाशन हैं, लेकिन उनमें कोई भी उसका मुखपत्र नहीं है।

संघ का दृष्टिकोण नहीं | दूसरा, संघ का आधिकारिक मत केवल सरसंघचालक और सरकार्यवाह व्यक्त करते हैं। इसके अलावा कभी-कभी संघ अपने कुछ अधिकारियों को औपचारिक रूप से मीडिया से बात करने के लिए या सार्वजनिक रूप से अपना मत रखने के लिए अधिकृत करता है। चर्चा में आए इस आलेख को लिखने वाले या प्रकाशित करने वाले इन तीनों श्रेणियों में नहीं आते। इसलिए इसे संघ का दृष्टिकोण मानना तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है।

क्या है सच
- भागवत का बयान BJP केंद्रित नहीं था
- संघ का कोई अधिकृत मुखपत्र नहीं है
- विरोधियों ने भ्रम फैलाने में मदद की

मर्यादा पालन की सीख | जहां तक सरसंघचालक के भाषण का प्रश्न है तो उनकी इस टिप्पणी को कुछ विश्लेषकों ने BJP और नरेंद्र मोदी पर तंज करार दिया, 'जो सेवा करता है, जो वास्तविक सेवक है, जिसको वास्तविक सेवक कहा जा सकता है, उसकी कोई मर्यादा रहती है यानी वह मर्यादा से चलता है। काम सब लोग करते हैं, लेकिन कार्य करते समय मर्यादा का पालन करना।..... उस मर्यादा का पालन करके जो चलता है, कर्म करता है, कर्मों में लिप्त नहीं होता, उसमें अहंकार नहीं आता, वही सेवक कहलाने का अधिकारी होता है।'

बयान का अचर्चित हिस्सा | जो विवाद खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया कि भागवत ने इस टिप्पणी के साथ ही यह भी कहा जिससे उनका पूरा मंतव्य स्पष्ट होता है, 'मेरे मन में आया कि अपना विचार क्या है, संघ कैसे चलता है, उसको बताने का दूसरा कौन सा उपाय है? सरल उपाय यही है।' उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो बात उन्होंने उदाहरण सहित कही उन 'पंक्तियों में संघ की वृत्ति ध्यान में आती है क्योंकि इन बातों में उलझे रहेंगे तो काम रह जाएंगे।' यानी यह स्पष्ट है कि वह संघ के स्वयंसेवकों की ओर इशारा कर यह बात कह रहे थे और संघ के काम करने के ढंग की जानकारी दे रहे थे न कि BJP या सरकार को कोई सीख दे रहे थे।

PTI

राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर RSS चीफ मोहन भागवत और PM नरेंद्र मोदी

राजनीति का गिरता स्तर | इसी भाषण में उन्होंने चुनावों और मौजूदा विमर्श को लेकर जो बात कही, वह भारतीय राजनीति के बदलते स्वरूप को लेकर थी। क्या यह बात सच नहीं कि सामान्य नागरिक महसूस कर रहे हैं कि हमारे देश की राजनीतिक पार्टियों में पारस्परिक आलोचना का स्तर गिरता जा रहा है? BJP और संघ के अधिकारियों के 'डीप फेक' विडियो बना कर सोशल मीडिया पर डाले गए। यह भी सबने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान राजनीतिक लाभ के लिए एक मिथ्याजाल बुना गया कि चार सौ पार करने के बाद BJP संविधान बदल कर आरक्षण समाप्त कर देगी।

डीपफेक विडियो | सरसंघचालक ने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रचार के दौरान तकनीक का इस्तेमाल कर संघ के नाम से मिथ्या प्रचार करने का प्रयास भी हुआ। इस संदर्भ में अब सरसंघचालक की इस टिप्पणी को देखेंगे तो स्थिति और स्पष्ट होगी कि जो उन्होंने कहा वह किसके लिए था: 'ये स्पर्धा है, कोई आपस का युद्ध नहीं है। जिस प्रकार ये बातें हुई, जिस प्रकार एक दूसरे को लताड़ना हुआ, इस प्रकार प्रचार के दौरान हमारे करने से समाज में मनमुटाव बढ़ेगा, समाज दो गुटों में बंटेंगे, आपस में शंका-संशय उत्पन्न होगा, इसका भी ख्याल नहीं रखा गया। बिना कारण संघ जैसे संगठनों को भी उसमें खींचा गया। टेक्नॉलजी का सहारा लेकर असत्य बातें परोसी गईं। नितांत असत्य। क्या शास्त्र का, विज्ञान का, विद्या का यह उपयोग है? सज्जन विद्या का ये उपयोग नहीं करते।'

सुधार की जरूरत | वास्तव में सरसंघचालक के भाषण में संकेत इस बात का था कि हमें अपनी राजनीतिक संस्कृति में समग्र सुधार की आवश्यकता है और सभी राजनीतिक दलों को इसके लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट कहा, 'पिछले दस वर्षों में बहुत कुछ अच्छा हुआ।... लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम चुनौतियों से मुक्त हो गए।' सरसंघचालक का स्पष्ट संदेश था कि चुनौतियों का सामना करने और भारत को विकास के पथ पर आगे ले जाने का काम राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण प्रभावित नहीं होना चाहिए।

(लेखक RSS पर दो पुस्तकें लिख चुके हैं)

तैयारी पेरिस जीत लेने की

2020 तोक्यो ओलिंपिक में रेकॉर्ड तोड़ परिणामों के बाद भारत को पेरिस ओलिंपिक 2024 की मेडल लिस्ट में दोहरे अंकों की उम्मीद है। इसके लिए कई भारतीय खिलाड़ी विदेशी ट्रेनिंग कैंपों में जी-जान से जुटे हैं। सरकार ने इन एथलीटों को पेरिस के लिए पूरी तरह से तैयार करने के लिए करोड़ों रुपये का बजट भी जारी किया है। देखते हैं कि देश के लिए कौन कहां पसीना बहा रहा है :

बजट- मिशन ओलिंपिक सेल, टारगेट ओलिंपिक पोडियम स्कीम के जरिए एथलीटों को बेहतरीन विदेशी अनुभव देने के लिए 17.90 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है।

भारत की उम्मीद

नीरज चोपड़ा - जैवलिन थ्रो
अदिति अशोक- गोल्फ
सात्विकसाईराज रंकीरेड्डी - चिराग शेट्टी- बैडमिंटन
निखत जरीन- बॉक्सिंग
पीवी सिंधु- बैडमिंटन
पुरुष हॉकी टीम
लवलीना बोरगोहेन- बॉक्सिंग

नीरज चोपड़ा *(साउथ अफ्रीका, फिनलैंड, जर्मनी, तुर्किये)*
48.76 लाख खर्च 176 दिनों में

ट्रैक रेकॉर्ड
- 2021 में तोक्यो ओलिंपिक में गोल्ड मेडल।
- 2022 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप सिल्वर मेडल।

पीवी सिंधु *(जर्मनी)*
26.60 लाख खर्च/36 दिन

ट्रैक रेकॉर्ड
- ओलंपिक और BWF सर्किट में मेडल
- 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल
- 2020 समर ओलिंपिक (तोक्यो) में ब्रॉन्ज
- 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल
- 2013 में अर्जुन अवार्ड

मीराबाई चानू *(सेंट लुईस- अमेरिका)*
42.54 लाख खर्च/ 65 दिन

ट्रैक रेकॉर्ड
- 2021 तोक्यो ओलिंपिक में सिल्वर मेडल।
- 2022 बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल।

अविनाश साबले, पारुल चौधरी और हरमिलन बैंस *(कोलोराडो स्प्रिंग्स अमेरिका)*
1.79 करोड़ खर्च/ 107 दिन

विनेश फोगाट *(बुल्गारिया, हंगरी, किर्गिस्तान, स्पेन, फ्रांस)*
33.07 लाख खर्च/ 97 दिन

ट्रैक रेकॉर्ड
- राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल।
- विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में कई मेडल।

रोहन बोपन्ना *(अमेरिका,मोनाको, स्पेन, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन)*
1.03 करोड़ खर्च/ 181 दिन

ट्रैक रेकॉर्ड
- दो ग्रैंड स्लैम खिताब।
- 2012 और 2016 के ओलिंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व।

निशद कुमार, मरियप्पन थंगावेलु *(चुला विस्ता, अमेरिका)*
39.83 लाख खर्च/ 75 दिन

शरथ कमल *(डसेलडॉर्फ, जर्मनी)*
6.20 लाख खर्च
44 दिन

लवलीना बोरगोहेन *(चेक रिपब्लिक)*
4.41 लाख खर्च 6 दिन

ट्रैक रेकॉर्ड
- तोक्यो ओलिंपिक ब्रॉन्ज मेडल।
- देश की तीसरी ओलिंपिक विनर।

लक्ष्य सेन *(मार्सिले-फ्रांस)*
9.33 लाख खर्च/ 14 दिन
- पूर्व वर्ल्ड जूनियर नंबर 1 हैं।
- वर्ल्ड चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज विनर

पेरिस पॉइंटर्स
- तोक्यो ओलंपिक में भारत ने एक गोल्ड सहित सात पदक जीते थे।
- अभी तक पुरुष हॉकी टीम सहित 83 भारतीय खिलाड़ी ओलिंपिक में चयनित।
- अब तक नीरज सहित 12 पुरुष और 7 महिला एथलीट क्वॉलिफाई।
- पेरिस ओलिंपिक में आएंगे 10,500 खिलाड़ी

कंटेंट: राहुल पाण्डेय

Graphics & Images : AI

कहां कितना खर्च

एथलेटिक्स	बैडमिंटन	शूटिंग	टेनिस	पैरा स्पोर्ट्स	कुश्ती	भारोत्तोलन	मुक्केबाजी	तीरंदाजी	तैराकी	घुड़सवारी
6.25cr	5.77cr	3.83cr	1.57cr	1.17cr	0.55cr	0.42cr	0.36cr	0.20cr	0.15cr	0.07cr

पूरी होगी यूनिवर्सल डोनर ब्लड की आशा?

मुकुल व्यास

अस्पतालों में जरूरतमंद मरीजों के लिए ब्लड जुटाना हमेशा मुश्किल होता है। वैज्ञानिक लंबे समय से ऐसे यूनिवर्सल डोनर ब्लड की तलाश में हैं, जो किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सके। अब वैज्ञानिकों ने आंत के बैक्टीरिया का उपयोग करके इस दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। 'नेचर माइक्रोबायॉलजी' पत्रिका में प्रकाशित नया अध्ययन बताता है कि शोधकर्ताओं ने शुगर के मॉलिक्यूल की लंबी श्रृंखला की पहचान की है जो इस समस्या के समाधान में काफी मददगार हो सकता है।

एंटीजन का खेल | गलत खून चढ़ाने से घातक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हो सकती है। इसकी वजह यह है कि इम्यून सिस्टम RBC से निकलने वाले बाहरी शुगर मॉलिक्यूल या एंटीजन को पहचान लेता है और उन पर हमला शुरू कर देता है। A टाइप के ब्लड में A एंटीजन, B टाइप के ब्लड में B एंटीजन के साथ मिश्रित नहीं होते। यूनिवर्सल डोनर ग्रुप O में इन एंटीजन की कमी होती है। यही वजह है कि इसे किसी भी ब्लड टाइप वाले में चढ़ाया जा सकता है।

असंगति से मदद | पिछले कई दशकों से वैज्ञानिक A और B ब्लड ग्रुप में एंजाइमों की मदद से एंटीजन हटाने की कोशिश कर रहे हैं। 1980 के दशक में टाइप B ब्लड को टाइप O में चेंज करने के लिए बिना भुनी हुई कॉफी बीन्स से प्राप्त एंजाइमों का उपयोग शुरू किया। तबसे वैज्ञानिकों ने और बेहतर एंजाइम खोजे हैं जो A और B, दोनों टाइप के ब्लड में काम करते हैं।

खोज में पता चला | RBC से एंटीजन साफ करने के बाद, टाइप A और टाइप B, दोनों ब्लड के अणु टाइप O रक्त की तरह दिखते हैं। लेकिन जब इस उपचारित ब्लड को टाइप O ब्लड प्लाज्माके साथ मिलाया गया तो सकारात्मक प्रतिक्रिया दिखी। यह असंगति का संकेत था। वैज्ञानिकों ने विस्तृत जांच करने के बाद पाया कि A और B टाइप से एंटीजन हटाने के बावजूद उनमें शुगर के मॉलिक्यूल की लंबी श्रृंखलाएं मौजूद थीं। उनकी उपस्थिति से यह असंगति पैदा हुई।

AI Image

एंजाइम का कॉकटेल | नए अध्ययन में स्वीडन के वैज्ञानिक मार्टिन ओल्सन ने दिखाया कि टाइप A और B ब्लड से एंटीजन और शुगर के एक्सटेंशन को हटाने से यह टाइप O ब्लड के साथ अधिक अनुकूल हो जाता है। उनकी टीम ने अक्करमेंसिया म्यूसिनीफिला नामक बैक्टीरिया से एंजाइमों के एक कॉकटेल का उपयोग किया।

शुगर एक्सटेंशन का असर | यह बैक्टीरिया मानव आंत में पाया जाता है। बैक्टीरिया आंत की म्यूकस लाइनिंग (चिपचिपी परत) में शुगर की लंबी श्रृंखलाओं को विखंडित कर देता है। जब वैज्ञानिकों ने टाइप B ब्लड में मूल एंटीजन को हटा कर उसका टाइप O प्लाज्मा के साथ प्रयोगशाला में परीक्षण किया, तो लगभग 80% B डोनर प्लाज्मा को टाइप O प्लाज्मा के साथ संगत पाया गया। ऑब्जर्वेशन करने पर पाया गया कि एक बार शुगर का एक्सटेंशन हटाने के बाद यह मात्रा लगभग 91% से 196% तक बढ़ गई। इससे पता चला कि शुगर के एक्सटेंशन ने प्रारंभिक असंगति में योगदान दिया होगा।

पहला ठोस कदम | हालांकि A ब्लड ग्रुप के लिए परिणाम उतने अच्छे नहीं हैं। कोलंबिया विश्वविद्यालय के डॉ. स्टीवन स्पिटलनिक ने कहा कि टाइप A, टाइप B की तुलना में जैव-रासायनिक रूप से अधिक जटिल प्रतीत होता है। इसलिए वैज्ञानिकों को एंजाइमों के अपने कॉकटेल को संशोधित करना पड़ेगा। इस विधि को पर्याप्त रूप से सुरक्षित बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। फिर भी यह यूनिवर्सल डोनर ब्लड की दिशा में पहला ठोस कदम है।

कॉमन रूम

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें hindi.speakingtree.in

बार-बार शिकायत करने से संबंधों में दरार आ जाती है

निर्मल जैन

मैं अंधेरे कमरे में हूं फिर भी मुझे खुशी है कि देखने के लिए मेरे पास आंखें हैं। मैं खुश हूं कि मेरा बैंक बैलंस भले ही बहुत ज्यादा न हो, मेरे पास इतनी सुविधा है कि किसी को कुछ देकर उसके मुख पर मुस्कान लाने का जरिया बन सकता हूं। भगवान बनने की पात्रता मुझमें नहीं है, पर शैतान बनने के गुनाह से मैं बच गया हूं। जो नहीं मिला, उससे कोई शिकायत नहीं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपने मन को सदा इसी प्रकार से आभार प्रकट करने वाली वृत्ति से ओत-प्रोत रखूं।

अक्सर ऐसा होता है कि जो सुविधा हमें अबाध रूप से मिलती चली आ रही है, उसमें थोड़ा भी व्यवधान आ जाए तो जो मिला है उसके प्रति आभार प्रकट करने के बजाय हम कुछ समय के व्यवधान को लेकर आक्रोश से भर उठते हैं। अजीब विडंबना है कि दूसरों के माध्यम से मिलने वाली सुख-सुविधाओं के लिए हमारा मन कभी आभारी नहीं बनता, बल्कि उन्हें अपना अधिकार समझने लगता है। लेकिन प्राप्त सुविधाओं में कमी आती है तो न केवल गिला-शिकवा करते हैं, बल्कि दूसरों को दोषी भी ठहरा देते हैं। परिणाम होता है कि जब भी हमारा मन शिकायत करता है, जीवन में उपालंभ, तानाकशी और निंदा का सिलसिला ही शुरू हो जाता है। शिकायत करना अपने आप में नकारात्मक वृत्ति का सूचक है। शिकायत वाले मन के साथ बहुत दूर नहीं चला जा सकता। स्वभाव की कोमलता, स्नेह इसके साथ नहीं ठहरते, तनाव के झोंके बार-बार असहज करते रहते हैं। असुविधा सहने का अभ्यास जरूरी है। हम बच्चों को हमेशा समझाते रहते हैं कि जिद मत करो, जो मिल रहा है उससे संतुष्ट रहो, लेकिन स्वयं इसके विपरीत व्यवहार करते हैं।

महात्मा बुद्ध के मठ में एक नए शिष्य ने चार दिन में तीन बार भोजन, बिस्तर, अपने साथी के व्यवहार को लेकर शिकायत की। बुद्ध ने कहा, 'चार दिन में तीन शिकायतें। इसका मतलब यह स्थान तुम्हारे लिए सही नहीं है।' उन्होंने समझाया, 'बिना कष्ट के कुछ भी हासिल करना संभव नहीं, लक्ष्य जितना बड़ा होता है, असुविधा भी उसी अनुपात में बढ़ जाती है।'

आभार प्रकट करना, धन्यवाद देना हमारी सकारात्मकता की पहचान है। बात-बात में शिकायत करना, अपनी मजबूरी बताकर औरों की सहानुभूति का चंदा इकट्ठा करना कुछ लोगों का स्वभाव सा बन जाता है। ऐसा करना, दरअसल जीवन को बोझ के रूप में ढोते रहना है। शिकायत की वृत्ति संबंधों में भी दीवार का काम करती है। मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। शिकवा, गिला, शिकायत के चक्रव्यूह में प्रवेश कर हमें हर समय यह अनुभव होता रहता है कि जिस हालत में हम जी रहे हैं वह औरों की अपेक्षा अधिक कष्टदायक है। इसलिए मित्र, स्वजन, स्नेही सभी के प्रति शिकायतों के स्वर उभरते हैं।

आभारी होना, धन्यवाद देना चंदन की भांति है। धन्यवाद देकर हम भार उतार लेते हैं और हल्का महसूस करते हुए खुश हो जाते हैं। जिसके प्रति धन्यवाद करते हैं उसके हृदय में भी मृदु भावों के संस्पर्श से सकारात्मकता का स्रोत खुल जाता है। जहां धन्यवाद है, आभार है, वहां प्रेम है। जहां शिकायत है, वहां वैमनस्य है। उपकारी व्यक्ति एक ऐसे पुल के समान होते हैं जो आभार या धन्यवाद के दूरदर्शी यंत्र से दूरियों को भी नजदीकी में बदल देते हैं।

आर.एन.आई. नं. 510/57© सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। स्वत्वाधिकारी बैनेट, कोलमैन एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लिए राजीव यादव द्वारा, 7 बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित तथा **टाइम्स ऑफ इंडिया प्रेस, साइट IV, औद्योगिक क्षेत्र साहिबाबाद** और प्लॉट नंबर 7-8, सेक्टर M-11, ट्रांसपोर्ट हब, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, मानेसर, हरियाणा से मुद्रित। फोन : 23302000 फैक्सः 23492047, पंजीकृत कार्यालय : दादाभाई नौरोजी रोड, मुंबई-400001। विमान सेवा शुल्क : 1 रु. प्रति कॉपी। नेपाल में कुल मूल्य : सोमवार से शनिवार : नेपाली 5 रु.; रविवार : नेपाली 6 रु.
संपादक (दिल्ली मार्केट) : आशीष पांडे (इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी)

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 17 अंक 106

सुरक्षा को मिले प्राथमिकता

कोलकाता के सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस और एक मालगाड़ी के बीच उत्तरी बंगाल में हुई भिड़ंत बताती है कि भारतीय रेल ने महज एक साल पहले ओडिशा के बालासोर में हुई तीन ट्रेनों की भिड़ंत से कोई सबक नहीं लिया। उस दुर्घटना में बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए थे। वह हादसा बीते कई दशकों का सबसे बुरा रेल हादसा था और उसका कारण सिग्नल प्रणाली में गड़बड़ी थी। कंचनजंगा एक्सप्रेस मामले में भी रेलवे की प्राथमिक जांच से यही संकेत निकलता है कि यह दुर्घटना स्वचालित सिग्नल प्रणाली में गड़बड़ी और मालगाड़ी के चालक (अब मृत) द्वारा गति संबंधी नियमों के उल्लंघन के कारण हुई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हुई और 50 से अधिक लोग घायल हुए।

खुशकिस्मती से कंचनजंगा एक्सप्रेस के पिछले डिब्बे पार्सल कोच थे जिसके चलते हादसे का असर सीमित रहा। सिग्नल प्रणाली की गड़बड़ी के कारण अगरतला और कोलकाता के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन और मालगाड़ी दोनों को अनियार्य लिखित आदेश दिया गया था जो चालकों को मानक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पर्यवेक्षण करने के बाद स्वचालित रेड सिग्नल को पार करने की बात कहता है। इसमें ट्रेन को सिग्नल के आगे एक स्टॉप तक लाना, दिन में एक मिनट तथा रात में दो मिनट प्रतीक्षा करना तथा उसके बाद गार्ड की पुष्टि के बाद 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से आगे बढ़ने की इजाजत होती है और पीछे वाली ट्रेन से 150 मीटर का अंतर उस स्थिति में हो जबकि उस ट्रेन ने सिग्नल को पार न किया हो। जांच के मुताबिक मालगाड़ी के चालक ने गति सीमा पर ध्यान नहीं दिया और उसकी ट्रेन कंचनजंगा एक्सप्रेस में पीछे से टकरा गई। कंचनजंगा एक्सप्रेस नौ सिग्नल पार कर चुकी थी और आगे बढ़ने के लिए सिग्नल की प्रतीक्षा में थी।

मानव त्रुटि हो अथवा नहीं लेकिन दुर्घटनाएं अक्सर इस बारे में प्रश्न उत्पन्न करती हैं कि रेलवे बुनियादी चीजों पर कितना ध्यान दे रहा है। गत वर्ष बालासोर में हुए हादसे की तरह ही इस लाइन पर भी भारतीय रेल के रिसर्च डिजाइंस ऐंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गनाइजेशन द्वारा विकसित स्वचालित ट्रेन संरक्षण व्यवस्था 'कवच' संचालित नहीं थी। इस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को इस प्रकार डिजाइन किया जाता है ताकि अगर चालक गति संबंधी नियमों का पालन नहीं कर सके तो ट्रेन में खुद ब खुद ब्रेक लग जाए। परंतु यह प्रणाली अब तक केवल 1,500 किलोमीटर ट्रैक पर ही संचालित है। रेलवे का कुल ट्रैक नेटवर्क 99,000 किलोमीटर का है और इस वर्ष इसमें 3,000 किमी की नई क्षमता शामिल होने वाली है। इस धीमी गति पर सवाल उठना लाजिमी है, खासकर तब जबकि रेलवे संचालन में सिग्नल की विफलता के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। रेलवे के पूंजीगत व्यय में भारी इजाफा हुआ है और उसे सुरक्षा पर पर्याप्त ध्यान देना ही चाहिए। यह सही है कि बीते दो दशकों में ऐसी ट्रेन दुर्घटनाओं में 90 फीसदी तक की कमी आई है जिनमें लोग हताहत होते हैं और जहां रेलवे की संपत्ति का नुकसान होता है। परंतु 2023 तक के पांच वर्षों में हर साल ऐसी 44 रेल दुर्घटनाएं हुईं यानी औसतन हर महीने तीन से चार दुर्घटनाएं। ऐसे में रेल यात्रा को पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता है। इसकी तुलना में इस सदी में कुछ ही हवाई दुर्घटनाएं हुई हैं। यकीनन देश की 90 फीसदी आबादी जो दुनिया के सबसे बड़े परिवहन माध्यम यानी रेल का इस्तेमाल करती है, उसे भी ऐसी ही सुरक्षा मिलनी चाहिए।

अजय मोहंती

भारत में समावेशी विकास और इससे जुड़ी चुनौतियां

नई सरकार के कार्यकाल में समावेशी विकास की नीति देश को ब्राजील के बजाय जापान की तरह तरक्की करने की राह पर ले जाएगी। बता रहे हैं रथिन राय

भारत में नई सरकार का गठन हो गया है। अब सरकार के समक्ष कई गंभीर आर्थिक चुनौतियां हैं जिनका प्रभावी ढंग से समाधान होने पर ही भारत विकास यात्रा पर निर्बाध रूप से आगे बढ़ सकता है।

सबसे पहले चुनौती रोजगार के अभाव से जुड़ी है। वर्ष 2014 के बाद चार चीजें बदतर हो गई हैं। ये बिगड़े हालात की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार की तरफ से गंभीर प्रयास की आवश्यकता है। पहली बात, देश में 18 से 35 वर्ष के दायरे में 10 करोड़ लोग रोजगार तलाश नहीं कर रहे हैं और न ही उनके पास शिक्षा या किसी तरह का प्रशिक्षण है। दूसरी बात, देश के श्रम बल का 45 प्रतिशत हिस्सा जीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तीसरी बात, उत्तरी राज्यों से दक्षिणी राज्यों और देशभर से विदेश की तरफ पलायन स्थिर एवं सुरक्षित जीवन के लिए सबसे आकर्षक विकल्प बना हुआ है। चौथी बात, दूसरा सबसे प्रमुख आकर्षण सरकारी नौकरी के प्रति है जिसे पाने के चक्कर में लाखों युवा अपना समय बरबाद कर रहे हैं।

वर्तमान स्थिति में सरकार ने उन लोगों के लिए मुआवजे का प्रावधान कर रखा है जो कहीं पलायन नहीं कर पा रहे या सरकारी नौकरी में नहीं आ रहे हैं। कृषि क्षेत्र में लगे लोगों को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का सहारा दिया जा रहा है। सभी तरह की सब्सिडी और नकदी अंतरण से यह योजना इन लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों का महज कुछ हिस्सा खरीदने में मदद मिल रही है। इसका परिणाम यह है कि देश लचर कृषि क्षेत्र, 90 प्रतिशत अनौपचारिक अर्थव्यवस्था और लगभग विनिर्माण उद्योग विहीन उत्तर एवं पूर्व (जहां देश की अधिकांश आबादी रहती है) जैसी चुनौतियों से उलझ कर रह गया है।

दूसरी चुनौती उपभोग/खपत से जुड़ी है। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में उपभोग में वृद्धि पिछले कुछ समय से कमजोर रही है। खतरनाक बात तो यह है कि उपभोग का एक बड़ा हिस्सा ऋणों पर टिका हुआ है। दूसरी तरफ, महंगी वस्तुओं का उपभोग बेरोकटोक बढ़ता ही जा रहा है। वाहन जैसे क्षेत्रों में महंगी कारें बिक्री बढ़ा रही हैं, न कि सस्ती कारें। हवाई यात्रा की बढ़ती मांग के बीच रेल सेवा जरूरत के हिसाब से सीमित की जा रही है। न्यूनतम वेतन पाने वाले लोगों के लिए ईंधन और बिजली की तरह आवास की व्यवस्था भी सब्सिडी के दम पर ही हो पाएगी। दुनिया में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था में अधिकांश लोग ऋण, सब्सिडी के बिना बेहतर और आर्थिक रूप से सुरक्षित जीवन जीने की हालत में नहीं हैं।

तीसरी चुनौती उत्पादकता से जुड़ी है। मेरे विचार से यह समस्या असमानता का संकेत है और इसका तार समाज से जुड़ा हुआ है। इस चुनौती से निपटने के लिए सामूहिक रूप से प्रयास करना होगा। उत्तर प्रदेश और बिहार नेपाल से गरीब हैं। इन दोनों राज्यों से श्रम एवं पूंजी का प्रवाह देश के पश्चिमी और दक्षिणी राज्यों में होता है। इसका मतलब है कि ऐसे लोगों के मूल स्थानों या राज्यों में विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों से जुड़ी नौकरियां नहीं होने के कारण उन्हें देश के दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए पलायन करना पड़ रहा है। आधारभूत ढांचे का इस्तेमाल सामान तटीय बंदरगाहों तक ले जाने के लिए न होकर लोगों को एक से दूसरे स्थान तक पहुंचाने (कोविड महामारी का वाकया तो जरूर याद होगा) के लिए हो रहा है। जाति, धर्म एवं लिंग भी उत्पादकता पर असर डालते हैं। भाई-भतीजावाद और अपराधशीलता प्रवृत्ति को समाज में संचय और संपन्नता के बजाय स्थान मिलना स्थिति को और भयावह बना रहा है।

ये भारत के विकास की राह में गंभीर, बदतर होती और लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां हैं। मगर ये मुद्दे चुनाव में अधिक प्रभावी नहीं दिखे और न ही नतीजों में इनकी स्पष्ट छाप मिली। चुनाव के बाद जनता के फैसले यानी नतीजों में विविधता यह बात स्पष्ट करती है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में नुकसान उठाना पड़ा वहीं, इंडी गठबंधन (इंडिया) को इन दोनों राज्यों में बढ़त मिली मगर बिहार और तेलंगाना में इसका उल्टा हुआ। यह इस बात का संकेत है कि विकास से जुड़े मुद्दे मौजूदा चुनावों के लिए प्रत्यक्ष तौर पर मायने नहीं रखते हैं।

अगर चुनावी राजनीति इस प्रतिस्पर्द्धा के इर्द-गिर्द घूमती है कि कौन बेहतर क्षतिपूरक राज्य दे सकता है या आर्थिक अवसर हाथ से निकलने की भरपाई बेहतर तरीके से कौन कर सकता है तो फिर चुनौतियां कम नहीं होंगी। इनके साथ अगर संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन और राजनीतिक समावेशन लगातार विवाद में रहते हैं तो देश वास्तविक रूप से कभी विकासोन्मुख नहीं हो पाएगा।

राजनीतिक तंत्र इन व्यापक चुनौतियों से बेपरवाह है और केवल राजकोषीय घाटे एवं रीपो दर में मामूली बदलाव और कर से जुड़े विषयों पर बहस करने से ही संतुष्ट है। इन बातों में बेवजह समय बरबाद न कर नीति निर्धारकों को वर्तमान समय की चुनौतियों को दूर करने पर ध्यान देना चाहिए। मगर देश में इन चुनौतियों से निपटने वाले लोग तभी आएंगे जब राजनीतिज्ञ बदलाव लाने की दिशा में काम करेंगे और एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे जो राष्ट्र के विकास के लिए सामूहिक प्रयासों को बढ़ावा देने में सक्षम होगी।

एक ऐसी औद्योगिक नीति पर विचार किया जाना चाहिए जिससे विनिर्माण में नयापन आए और औपचारिक आर्थिक गतिविधियों की हिस्सेदारी बढ़ सके। न्यूनतम वेतन अर्जित करने वालों की घरों की जरूरत पूरी करने के लिए मध्यम अवधि की योजना जरूरी है। केवल निर्यात और यूनिकॉर्न (एक अरब डॉलर से अधिक मूल्यांकन वाली स्टार्टअप इकाई) को लेकर खुशफहमी में रहने से काम नहीं चलेगा। राष्ट्रीय आय में वेतन की शिथिल पड़ी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए एक सक्रिय आय नीति की आवश्यकता है। इसके साथ ही एक ऐसी नीति की भी जरूरत है जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और आर्थिक दृष्टिकोण से स्थिर एवं लाभकारी कृषि क्षेत्र के हितों को शहरी क्षेत्रों में बड़बोलापन दिखाने वाले लोगों को सस्ता भोजन देकर हमेशा सूली पर नहीं चढ़ाया जाना चाहिए। इस तरह के विचार राजनीतिक बहस का हिस्सा होना चाहिए और संसद में इन पर चर्चा होनी चाहिए। मगर ऐसा नहीं हो पा रहा है।

चुनावों में अधिक वजूद नहीं मिलने और पहले से मौजूद मुद्दों पर मची तकरार के बावजूद मैं लगातार एक समावेशी विकास की राह पर सभी के साथ आने की उम्मीद कर रहा हूं। समावेशी विकास की यह नीति देश को ब्राजील के बजाय जापान की तरह तरक्की करने की राह पर ले जाएगी। लंबे समय से चले आ रहे विवादित मुद्दों के समाधान के लिए इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता। समावेशी विकास की नीति एक प्रभावी औजार है।

(लेखक कौटिल्य स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में प्राध्यापक और ओडीआई लंदन में अतिथि वरिष्ठ फेलो हैं।)

जलवायु परिवर्तन के दौर में एजेंडा

देश में एक बार फिर पांच साल के लिए नई सरकार का गठन हो गया है। मेरी नजर में इस सरकार का एजेंडा वही पुराना है लेकिन इसमें एक बुनियादी अंतर है। यह एजेंडा देश के विकास और जलवायु परिवर्तन के दौर को देखते हुए होना चाहिए। एक तथ्य यह भी है कि प्राथमिकता वाले कदमों के क्षेत्रों की सूची भी समान है। ऊर्जा से लेकर पानी और सफाई से लेकर खाद्य और पोषण तक लगभग हर क्षेत्र में हमारे काम अधूरे हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी यही स्थिति है। हमें पता है कि पिछली सरकार के पास योजनाएं थीं और उसने इन तमाम मुद्दों के लिए बजट भी आवंटित किया था।

हम यह भी जानते हैं कि जन कल्याण का काम एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इन चुनावों के दौरान जब संवाददाता मतदाताओं के विचार जानने निकले तो हमें सुनने को मिला कि बेरोजगारी एक अहम चिंता थी। स्वच्छ पेयजल की कमी और सफाई का अभाव भी एजेंडे में प्रमुख था। ऊर्जा संकट भी एक मुद्दा था क्योंकि घरेलू गैस सिलिंडर की कीमत जेबों पर भारी पड़ रही थी और बिजली की उपलब्धता के बारे में ठीक-ठीक कुछ नहीं कहा जा सकता था। किसान अभी भी संकट में हैं। यानी अभी काफी काम करना बाकी है और यह उन क्षेत्रों में है जिनके बारे में पिछली सरकार ने कहा कि वह इन पर काम कर रही है। इसमें चकित होने वाली कोई बात नहीं। भारत एक बहुत बड़ा देश है और यहां शासन के मोर्चे पर तमाम कमियां हैं। किसी भी सरकारी योजना का अंतिम लक्ष्य यही है कि वह हर बार लोगों तक पहुंचे। अब जलवायु परिवर्तन का असर भी इसमें जुड़ गया है क्योंकि लगभग रोज देश का कोई न कोई हिस्सा मौसम की अतिरंजित घटना से दो-चार होता है। इसका विकास कार्यक्रमों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बेमौसम बारिश और मौसम की अन्य अतिरंजित घटनाओं के कारण बाढ़, सूखा, आजीविका का नुकसान हुआ है और सरकारी संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव जैसे असर हुए हैं। यही वजह है कि भविष्य के एजेंडे में इस बात को स्वीकार किया जाना चाहिए कि विकास का संबंध पैमाने, गति और परिकल्पना से है। हमें विकास संबंधी योजनाओं के डिजाइन में और अधिक कल्पनाशीलता दिखाने की आवश्यकता है।

जमीनी हकीकत

सुनीता नारायण

लंबे समय तक सरकारें कल्याणकारी रुख तथा पूंजीवादी न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप के रुख के बीच उलझी रहीं। मेरी दृष्टि में जलवायु जोखिम के इस दौर में नए कथानक की आवश्यकता है। सरकार को विकास को लेकर नए सिरे से काम करने की जरूरत है ताकि वह समावेशी हो, सबके लिए लाभदायक और टिकाऊ हो। यानी हमें हर चीज को देखने को लेकर अपनी कल्पनाशीलता में बदलाव करना होगा। इसमें स्वच्छ जल की आपूर्ति से लेकर ऊर्जा तक शामिल है जिसका स्वच्छ लेकिन कम लागत वाला होना भी जरूरी है। इसके लिए डिजाइन और आपूर्ति में बदलाव लाना होगा। हमें धरती के लिए नई तरह का विकास प्रतिमान चाहिए जो सबके लिए कारगर हो। ध्यान देने वाली बात है कि अधिकांश मामलों में सरकार के पास योजनाएं और बजट है। हमें यह सीखने की जरूरत है कि क्या कारगर है और क्या नहीं। हमें ऐसे कदमों की जरूरत है जो बड़े बदलाव लाएं। इसके लिए क्रियान्वयन करना होगा और जैसा कि मैंने कहा इस दिशा में पूरे जुनून के साथ काम करना होगा।

यह सब तभी संभव होगा जब हम अगली पीढ़ी के दो सुधारों को अंजाम देना होगा। मेरी नजर में यह सरकार के लिए सबसे अहम एजेंडा होना चाहिए। पहला, हमें जमीनी संस्थानों को मजबूती देनी होगी जहां स्थानीय लोग हिस्सेदार हों। हमें भागीदारी वाले लोकतंत्र की आवश्यकता है ताकि विकास कार्यक्रम सफल हो सकें। जन संस्थानों मसलन ग्रामीण इलाकों में पंचायती राज और शहरी इलाकों में नगर निकायों को मजबूत बनाने के लिए पारित 73वें और 74वें संविधान संशोधन को 30 वर्ष बीत चुके हैं। हमने ग्राम सभाओं को मजबूत करके लोकतंत्र की पहुंच बढ़ाने के प्रयोग भी किए। परंतु यह सब अधूरा रह गया। हमें ग्रामीण और सरकारों को प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण दिलाने के लिए अहम प्रयास करने होंगे। जरूरत यह है कि वे फंड का प्रबंधन करें, पर्यावरण के अनुकूल रोजगार तैयार करें और आजीविका के लिए प्राकृतिक संसाधनों में निवेश करें।

हमें एक नए भारत के लिए संचालन संस्थानों को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। बीते कुछ वर्षों के दौरान अधिकांश पारंपरिक संस्थानों का क्षरण हुआ है। परंतु तथ्य यह है कि शासन और नियमन के लिए संस्थानों की आवश्यकता है जो जवाबदेही तय कर सकें और जो असहज करने वाले तथा कठिन निर्णयों से गुजर सकें। दूसरा, आज की तुलना में आने वाले समय में शासन को फीडबैक और जवाबदेही की अधिक आवश्यकता होगी। इसके लिए विभिन्न स्वरों के प्रति सहिष्णु होना होगा। यह समझना आवश्यक है कि वैकल्पिक सूचनाएं असहमति या आलोचना नहीं होतीं। हम जितना अधिक यह जानेंगे कि क्या कारगर है और क्या नहीं, शासन में उतना ही सुधार होगा। फिलहाल अधिकांश असहमत आवाज खामोश हैं। एक इको चैंबर जैसा माहौल है जहां केवल खुशामद करने वाले पनप रहे हैं। मेरी नजर में इससे सरकार कमजोर ही होती है। उसे कुछ सीखने को नहीं मिलता है और वह बहुत कम सीखती है। विश्वास बहाल करना सबसे महत्त्वपूर्ण है। यह न केवल योजनाओं की कामयाबी के लिए जरूरी है बल्कि समाज के विकास के लिए भी यह जरूरी है। यही एजेंडा होना चाहिए। यह वक्त बदलाव का है। हमें समाज को पर्यावरण के अनुकूल बनाना चाहिए क्योंकि यह समावेशी है और विकास को बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि यह टिकाऊ है।

(लेखिका सेंटर फॉर साइंस ऐंड एनवायरनमेंट से संबद्ध हैं)

आपका पक्ष

योजनाएं पूरी करने के लिए राज्यों से समन्वय जरूरी

नई सरकार को सबसे पहले पूंजीगत व्यय को अपनी प्राथमिकता में रखना होगा। यह राजस्व व्यय की तुलना में आर्थिक वृद्धि को ज्यादा गति देता है। बीते कुछ बजट इस तथ्य की पुष्टि करने वाले रहे हैं। इसलिए रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, बंदरगाह और जलमार्ग जैसे बुनियादी ढांचे में निवेश का दायरा और बढ़ाया जाना चाहिए। राज्य सरकारों के साथ बेहतर समन्वय भी बनाना होगा, जिनके अभाव में अक्सर परियोजनाएं लटक जाती हैं। जनसांख्यिकीय लाभांश की व्यापक संभावनाओं को भुनाने के लिए नई सरकार को स्कूली शिक्षा में सुधारों को मूर्त रूप देना चाहिए। देश में बीते तीन दशकों के आर्थिक उदारीकरण के दौर में लोगों की आकांक्षाओं में वृद्धि हुई है। विकसित भारत का नारा लोगों के सामने है। लेकिन यह हकीकत भी है कि बुनियादी ढांचे के निर्माण, नए रोजगार पैदा करने, कौशल विकास और लोगों के जीवन स्तर को बेहतर करने जैसे काम अभी शुरू ही हुए हैं। कई मोर्चों पर नीतियां अभी तय हुई हैं। जाहिर है, सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां बड़ी हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था अन्य क्षेत्रों में विकास के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पा रही है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सेहत को बहाल करना ही होगा और बुनियादी स्तर पर ही बहुत कुछ किए जाने की जरूरत है।

सुधीर कुमार सोमानी, देवास

बिहार के अररिया जिले के सिकटी प्रखंड में बकरा नदी पर बना पुल मंगलवार को ध्वस्त हो गया

राजकोषीय घाटा कम करना हो प्राथमिकता

नई सरकार को बेरोजगारी दूर करने, महंगाई को काबू में रखने और राजकोषीय घाटे को कम करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान देना होगा। भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी प्रशासन के साथ शिक्षा को रोजगार-रोन्मुखी बनाया जाए। सरकारी नौकरी पर निर्भरता कम हो। सरकार की प्राथमिकताओं में देश की रक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी, जनसंख्या संतुलन और रोजगार मूलक शिक्षा-व्यवस्था भी शामिल हो।

अंकित सोनी, मनावर

जनसंख्या नियंत्रण और रोजगार सृजन पर हो ध्यान

नई सरकार से सबसे बड़ी उम्मीद है कि उसे जनसंख्या नियंत्रण के लिए कुछ प्रावधान करने चाहिए। देश में रोजगार की कमी है। इसलिए नई सरकार को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास करने चाहिए। सरकार को देश में रेवड़ी संस्कृति पर अंकुश जरूर लगाना चाहिए।

हितेंद्र सिसोदिया, देवास

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार हो प्राथमिकता

देश की प्रगति का मूल आधार शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार है। किंतु इन्हें कभी भी गंभीरता से नहीं लिया गया। जब सरकार एक देश एक चुनाव की बात कहती है तो फिर एक देश एक समान शिक्षा पर भी विचार किया जाना चाहिए। एक देश,एक शिक्षा और एक जैसा पाठ्यक्रम और एक समान पाठ्य पुस्तकों का भी प्रावधान हो। इसी प्रकार देश की बहुसंख्यक जनता को बेहतर और एक समान स्वास्थ्य सुविधाएं देते हुए नवीन रोजगार सृजन को प्राथमिकता देना नई सरकार का लक्ष्य होना चाहिए।

हार्दिक जैन, इंदौर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी के पास एक मालगाड़ी से टकराने वाली कंचनजंगा एक्सप्रेस के अप्रभावित डिब्बे करीब 850 यात्रियों के साथ मंगलवार सुबह 3 बजकर 16 मिनट पर सियालदह स्टेशन पहुंचे। सोमवार को हुए हादसे में 10 लोगों की मौत हुई और कई घायल हो गए थे।

आतंकी हमले सुरक्षा चुनौतियां

हालिया आतंकी हमलों ने देश के समक्ष निरंतर जारी सुरक्षा चुनौतियों को रेखांकित किया है। जम्मू में हालिया आतंकी हमलों ने एक बार यह तथ्य उजागर कर दिया है कि आतंकवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। आतंकी भले ही कुछ समय के लिए परास्त हुए हैं, पर वे निश्चित रूप से अभी अपनी उपस्थिति बनाए हुए हैं। वास्तव में जम्मू में हुए कई हमले तीसरी बार सरकार बना रहे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रशासन के लिए गंभीर चेतावनी है। भू-राजनीतिक तनावों तथा सुरक्षा सरोकारों के दृष्टिकोण से जम्मू क्षेत्र हमेशा केन्द्र में रहा है। हाल ही में वह आतंकी हमलों के कारण सुर्खियों में आया है जिन्होंने स्थानीय जनता तथा सुरक्षा व्यवस्था को झटका दिया है। पिछले कुछ सप्ताह से आतंकी घटनायें बढ़ी हैं जिनमें सिविलियनों तथा सुरक्षा बलों पर 'लक्षित हमले' शामिल हैं जो क्षेत्र की क्षणभंगुर शांति की ओर इशारा कर रहे हैं। नवीनतम और सबसे गंभीर हमला जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में भारतीय वायुसेना के एक काफिले पर हुआ। इसमें एक वायुसैनिक शहीद हुआ तथा चार घायल हो गए। इन हिंसक घटनाओं के कारण न केवल मूल्यवान जीवन का विनाश हुआ, बल्कि निवासियों में भय और अनिश्चितता की आशंका भी पैदा हो गई। इन हमलों से जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का निरंतर व्याप्त तथा बढ़ता खतरा रेखांकित होता है जिससे निपटने के लिए तत्काल समग्र सुरक्षा उपाय जरूरी हैं। इन बढ़ते खतरों को देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में एक उच्चस्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई। शाह की समीक्षा में स्थिति की गंभीरता के साथ बढ़ते आतंकी खतरों के बोझ से निपटने के लिए बहुआयामी व सक्रिय दृष्टिकोण की आवश्यकता उजागर होती है।

हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि हमारी ओर से कोई कमी है जिससे आतंकियों में साहस पैदा होता है और वे ऐसी कार्रवाइयों की हिम्मत जुटाते हैं। आतंकवाद से मुकाबले में सबसे बड़ी कमी विभिन्न खुफिया एजेंसियों के बीच खुफिया सूचनाओं का बहुत कम साझा है। स्थानीय पुलिस बलों, भारतीय सेना तथा खुफिया एजेंसियों के बीच प्रभावी समन्वय समय पर हस्तक्षेप तथा भावी हमले रोकने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही स्थानीय समुदायों को विश्वास में ले कर आतंकी विभीषिका का मुकाबला करना चाहिए क्योंकि अक्सर नागरिक ही सबसे पहले असामान्य गतिविधियों पर गौर करते हैं और उनका सहयोग संभावित खतरों का समय से पहले मुकाबला करने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही आतंकवाद के मूल कारणों को संबोधित करना भी जरूरी है जिनमें सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर सबसे नीचे रहने वाले संकटग्रस्त लोगों का उग्रवादीकरण शामिल है। अक्सर आतंकी संगठन इन तत्वों का लाभ उठा कर लोगों को भर्ती कर हिंसा भड़काने में उनका प्रयोग करते हैं। हालांकि, जम्मू क्षेत्र में ज्यादा सैनिकों की तैनाती इस दिशा में स्वागत योग्य कदम है ताकि स्थानीय जनता सुरक्षा का अनुभव कर सके। जम्मू के भीतर सैनिकों की तैनाती शहरी केन्द्रों तथा ग्रामीण इलाकों में होनी चाहिए ताकि एक समग्र और व्यापक सुरक्षा उपस्थिति सुनिश्चित हो सके। लेकिन इस प्रकार सुरक्षा बढ़ाने की भी अपनी चुनौतियां हैं। यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि उग्रवादियों की उपस्थिति बढ़ने से स्थानीय जनता में तनाव तथा अलगाव की भावना न पैदा हो। सरकार को जीवन्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ाने तथा इन सुरक्षा उपायों से प्रभावित समुदायों में विश्वास और सहयोग की भावना पैदा करने के बीच संतुलन बनाना चाहिए।

योग और संगीत की शानदार संगति

शारीरिक बेहतरी तथा मानसिक शांति के लिए योग और संगीत की संगति बहुत शानदार है। इससे स्वास्थ्य एवं सामंजस्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण विकसित होता है।

राजदीप पाठक
(लेखक, गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति से संबद्ध हैं)

दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए 21 जून का विशेष महत्व है। इस दिन योग के प्राचीन विज्ञान तथा संगीत की सार्वभौमिक भाषा एक होती है। इससे बेहतरी और सामंजस्य का अनोखा संयोग पैदा होता है। इस दिन 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' तथा 'विश्व संगीत दिवस' मनाए जाते हैं। यह शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक बेहतरी के बीच सहयोग का विशिष्ट अवसर पैदा होता है। भारतीय संस्कृति और संगीत में गहरी जड़ें जमाए हुए योग स्वास्थ्य एवं प्रसन्नता के प्रति समग्र दृष्टिकोण पेश करता है। भारतवर्ष में 5000 साल से भी पहले जन्मे योग में शारीरिक आसनों, सांसों पर नियंत्रण, ध्यान तथा शरीर, मन एवं आत्मा के बीच सामंजस्य के नैतिक सिद्धान्तों को समाहित किया गया है। योग के सर्वाधिक प्राचीन संदर्भ ऋग्वेद में मिलते हैं जिनकी और विस्तृत व्याख्या उपनिषदों तथा भग्वद्गीता में की गई है। इसमें योग को 'स्व से स्व की यात्रा' के रूप में परिभाषित किया गया है। लगभग 400 वर्ष ईसापूर्व पातंजलि के 'योग सूत्रों' में व्यवस्थित रूप से योग के आठ आयामों को रेखांकित किया गया है जो शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक व्यवहारों का ढांचा प्रस्तुत करता है।

शताब्दियों तक योग का विकास विभिन्न योगियों और संतों के योगदान से हुआ। उन्होंने सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए अनेक योग शैलियों का विकास किया। योग की इन विभिन्न शैलियों में 'हठ योग', 'अष्टांग योग' तथा 'कुंडलिनी', आदि शामिल हैं। योग ने समकालीन समाज में सांस्कृतिक व भौगोलिक सीमायें पार की हैं तथा अपने अनेक स्वास्थ्य लाभों के कारण वैश्विक स्वीकार्यता प्राप्त की है। वैज्ञानिक शोध से शारीरिक फिटनेस सुधारने, मानसिक स्पष्टता तथा भावनात्मक दृढ़ता प्रदान करने में योग की प्रभावशीलता पुष्ट होती है। उदाहरणार्थ, 'यूरोपियन जर्नल आफ प्रिवेंटिव कार्डियोलोजी' जैसे सम्मानित जर्नलों में योग की क्षमता बताते हुए कहा गया है कि इससे कार्डियोवैस्कुलर स्वास्थ्य बेहतर होता है, ब्लड प्रेसर कम होता है, कोलेस्ट्राल स्तर तथा बाडी मास इंडेक्स संतुलित होता है।

'जर्नल आफ साइकियाट्रिक प्रैक्टिस' के अनुसार 'योग' अनेक अवसाद संबंधी विकृतियों की चिकित्सा में सहायक सिद्ध होता है। इसमें शारीरिक आसनों तथा ध्यान तकनीकों पर जोर देने के माध्यम से विचार क्षमता बढ़ती है, सांसों पर नियंत्रण स्थापित होता है, आंतरिक शांति व संकेन्द्रण सहज होता है और इस प्रकार संज्ञानात्मक क्षमतायें बढ़ती हैं। 'इंटरनेशनल जर्नल आफ योगा' के अनुसार योग से भावनात्मक नियमन बढ़ता है तथा संकेन्द्रित ध्यान व प्राणायाम से भावनात्मक स्थिरता तथा दृढ़ता स्थापित करने में सहायता मिलती है। आज दुनिया में लाखों लोग शारीरिक फिटनेस के लिए योग स्वीकार करते हैं तथा इससे स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए समग्र दृष्टिकोण विकसित होता है। उदाहरणार्थ, अमेरिका में योग में सहभागिता नाटकीय रूप से पिछले दशक में बढ़ी है तथा जनसंख्या का बड़ा हिस्सा नियमित योग करता है। इसी प्रकार यूरोप में योग को सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रमों तथा शैक्षिक पाठ्यक्रम से जोड़ कर समग्र बेहतरी में इसकी भूमिका पर जोर दिया गया है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव के बाद अब अंतरराष्ट्रीय योग दिवस एक वैश्विक आयोजन बन गया है। 177 देशों द्वारा सह-प्रायोजित इस प्रस्ताव में स्वास्थ्य और बेहतरी पर योग के समग्र लाभों पर जोर दिया गया है। इस दिवस का उद्देश्य योग पर वैश्विक जागरूकता बढ़ाना, इसके व्यवहार को प्रोत्साहित करना तथा शांति और एकता को बढ़ावा देना है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस ने अभूतपूर्व वैश्विक पहचान प्राप्त की है तथा आधुनिक दुनिया में योग की असीम प्रासांगिकता स्थापित की है। इसके साथ ही विश्व संगीत दिवस ने विविध रूपों में संगीत के आनन्द का उत्सव मनाया है। आहत भावनायें शांत करने और जनता को एकजुट करने में इसकी क्षमता रेखांकित हुई है। आज दुनिया भर में योग सत्रों, कार्यशालाओं तथा शैक्षिक आयोजनों का आयोजन हो रहा है जिससे योग का वैश्विक आकर्षण तथा सांस्कृतिक व राष्ट्रीय सीमाओं के पार जनता को एकजुट करने की इसकी क्षमता स्पष्ट होती है। इसी प्रकार 'विश्व संगीत दिवस' या 'फेट डी ला म्यूज़ीक' भी 21 जून को मनाया जाता है और यह अंतरराष्ट्रीय योग दिवस से मिलता है। एक सिद्धान्त के अनुसार 1981-82 में फ्रांस में जन्मा यह दिवस एक वैश्विक आयोजन में बदल गया है जो संगीत की सार्वभौमिक भाषा का आनन्द मनाने के प्रति प्रतिबद्ध है। इससे सार्वजनिक स्थलों पर सभी प्रकार के संगीतज्ञों को अपने प्रदर्शन का मौका मिलता है। ये आयोजन मुफ्त होते हैं तथा विविधतापूर्ण संगीतिक अभिव्यक्तियों को प्रोत्साहित करते हैं। आहत भावनायें शांति करने, एकजुट करने तथा लोगों को मानसिक रूप से ऊपर उठाने में विश्व संगीत दिवस एक सांस्कृतिक आयोजन के रूप में महत्वपूर्ण योगदान करता है। संगीत को लंबे समय से उसके 'चिकित्सकीय' प्रभावों के लिए जाना जाता है। इससे मानसिक स्वास्थ्य तथा भावनात्मक बेहतरी सुनिश्चित होती है।

शोध से स्पष्ट होता है कि संगीत से तनाव घटता है, दर्द से मुक्ति में सहायता मिलती है तथा संज्ञानात्मक क्षमता बढ़ती है। योग के संदर्भ में संगीत एक सुखद परिवेश प्रदान कर व्यवहार को समृद्ध बनाता है, संकेन्द्रण में वृद्धि होती है तथा गहराई से शांति को बढ़ावा मिलता है। योग और संगीत के समन्वय से बेहतरी प्रभावित होती है तथा मानसिक व भावनात्मक स्वास्थ्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण विकसित होता है।

सद्गुरु जग्गी वासुदेव ने एक बार कहा था, 'योग का अर्थ केवल झुकना और मुड़ना नहीं है। यह ऐसी स्थिति तैयार करने की प्रक्रिया है जहां आपका शरीर और मन प्रकृति एवं संगीत के साथ सामंजस्य स्थापित करता है।' इसे हर साल ईशा फाउंडेशन द्वारा आयोजित शिवरात्रि महोत्सव में देखा जा सकता है जिसमें संगीत, ध्यान और योग व्यवहारों का मिश्रण होता है। इस प्रकार योग और संगीत के बीच अंत: संबंध से व्यवहार बेहतर होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है तथा ध्यान की स्थिति को प्रोत्साहन मिल कर आंतरिक शांति स्थापित होती है। अग्रणी योग गुरु बी.के.एस. आयंगर ने कहा है कि 'योग प्राचीन, लेकिन संपूर्ण विज्ञान है और यह मानवता के विकास को लक्षित है।

इस विकास में सबकी बेहतरी शारीरिक स्वास्थ्य से आत्माभिव्यक्ति तक जाती है।' संगीत और योग व्यवहारों के समन्वय से समग्र विकास प्राप्त करने में सहायता मिलती है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है तथा भावनात्मक दृढ़ता मिलती है। फिजियोथेरेपिस्ट डा. प्रतीक्षा गडकरी ने जोर दिया है कि योग से जोड़ों का लचीलापन तथा उनकी गतिशीलता बढ़ाने में सहायता मिलती है। उन्होंने सुझाव दिया है कि व्यायाम के साथ संगीत को जोड़ने से ऊर्जा बढ़ती है तथा दिन की अच्छी शुरुआत होती है। प्रख्यात गायक, संगीत शिक्षक तथा नियमित योगाभ्यास करने वाले अमर कुलकर्णी ने योग और संगीत के बीच संबंधों का वर्णन करते हुए बताया है कि ये दोनों आंतरिक ऊर्जा तथा सकारात्मक गतिविधियों को प्रोत्साहित करते हैं।

कुछ योगाचार्यों के अनुसार कुछ योग शैलियों में संगीत शामिल करना उचित नहीं होगा। जहां 'विन्यास' व 'अनुसार' शैलियों में संगीत की व्यापक स्वीकार्यता है। इसके उलट आयंगर सत्रों में स्वर परिवेश मुख्यत: केवल शिक्षक के निर्देशों तक सीमित होता है। इस प्रकार यदि इस शैली में संगीत को शामिल किया जाए तो यह शिक्षक के निर्देशों में भ्रम पैदा कर सकता है। आज की तेजी से बदलती दुनिया में तनाव और मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे गंभीर हो रहे हैं। इनका प्रभाव अधिकांशत: नौजवानों पर पड़ता है। ऐसे में योग और संगीत का समन्वय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने तथा उसे पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। योग और संगीत एक साथ मिल कर बेहतरी व मानसिक शांति के साथ्न स्वास्थ्य व सामंजस्य के प्रति समग्र दृष्टिकोण विकसित कर सकते हैं।

क्रियाशील जीवन में विश्राम का महत्व

"व्यस्त दिनों के बीच में विराम लेने से मन और शरीर को रिचार्ज और फिर से ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है।"

साक्षी सेठी
(लेखिका, शिक्षाविद हैं)

क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो खुद को 24/7 उपलब्ध रखते हैं? या फिर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परिवार के साथ मिलकर समय बिताने के बजाय समय-समय पर सभी काम के मेल निपटाना पसंद करते हैं? अगर हां, तो दोस्तों, यह समय काम पर स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करने का है। व्यस्त दिनों के बीच में विराम लेने से मन और शरीर को रिचार्ज और फिर से ध्यान केंद्रित करने का मौका मिलता है।

विभिन्न अध्ययनों और शोधों के अनुसार, यह पाया गया है कि सबसे अधिक उत्पादक कर्मचारियों ने 52 मिनट तक काम किया है और उसके बाद 17 मिनट का ब्रेक लिया है। इसके अलावा अध्ययनों से यह भी पता चलता है कि किसी व्यक्ति का दिमाग लगातार काम करने के लिए नहीं बना है। उच्च प्रदर्शन को बनाए रखने और मानसिक थकान से बचने के लिए नियमित रूप से ब्रेक लेना ज़रूरी हो जाता है।

व्यक्ति की नौकरी प्रोफ़ाइल चाहे जो भी हो, नियमित रूप से ब्रेक लेना समग्र कार्य प्रदर्शन और सेहत को बढ़ाने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी रणनीति है। बिना ब्रेक के लगातार काम करने से बर्नआउट हो सकता है, जो थकावट और उत्पादकता में कमी की विशेषता है। ब्रेक मानसिक और शारीरिक रूप से रिचार्ज करने में मदद करते हैं। नियमित ब्रेक फोकस और एकाग्रता में सुधार करते हैं। समय-समय पर कार्यों से दूर रहने से व्यक्ति को स्पष्ट दिमाग और नई ऊर्जा के साथ वापस आने में मदद मिलती है। काम की दिनचर्या में ब्रेक को शामिल करके , कोई व्यक्ति उच्च उत्पादकता बनाए रख सकता है, तनाव को कम कर सकता है और अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। संक्षेप में, ब्रेक को प्राथमिकता देना उनके दीर्घकालिक करियर की सफलता और व्यक्तिगत खुशी में निवेश है क्योंकि यह रचनात्मकता और नवाचार को बढ़ावा दे सकता है। अक्सर यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति काम से विराम लेता है, तो उसका दिमाग घूमने और नए विचारों की खोज करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है और अप्रत्याशित समाधान की ओर ले जा सकता है।

कोविड-19 महामारी के बाद काम से ब्रेक लेने का महत्व और भी स्पष्ट हो गया है, क्योंकि कई कारकों ने लोगों के काम करने और जीने के तरीके को बदल दिया है। कोविड-19 महामारी ने बढ़ते तनाव, डिजिटल थकान और धुंधले कार्य-जीवन की सीमाओं को प्रबंधित करने के लिए काम से नियमित ब्रेक की आवश्यकता को बढ़ा दिया है। तेजी से बदलते कार्य वातावरण में उत्पादकता, रचनात्मकता, शारीरिक स्वास्थ्य और समग्र कल्याण को बनाए रखने के लिए ये ब्रेक आवश्यक हैं।

एक छोटी पारिवारिक छुट्टी या अगर छुट्टी नहीं है, तो कार्यदिवस या दोपहर के व्यायाम ब्रेक में माइक्रोब्रेक को शामिल करने जैसे नियमित ब्रेक को शामिल करने से कई लाभ हो सकते हैं, जिससे यह उत्पादकता और कल्याण दोनों को बनाए रखने के लिए एक सरल लेकिन प्रभावी रणनीति बन जाती है। जब कोई व्यक्ति सभी तरह के ब्रेक लेगा, तो वह उत्साह, खुशी, प्रसन्नता, प्रेरणा, गर्व और बहुत कुछ की सकारात्मक भावनाओं की तलाश करेगा जो अंतत: संज्ञानात्मक बहाली को बढ़ावा देगा।

इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति काम के तनाव में बहुत अधिक उलझ सकता है जब काम ही उसकी पहचान, मान्यता और आत्मविश्वास का एकमात्र स्रोत होता है, लेकिन कई बार व्यक्तियों के लिए उन गतिविधियों से संपर्क करना महत्वपूर्ण हो जाता है जो उनके पेशेवर जीवन से पूरी तरह से असंबंधित होती हैं जैसे कि कोई असंबंधित शौक या दोस्तों के समूहों के साथ गैर-काम के विषयों पर आकस्मिक बातचीत जो अक्सर हंसी, प्रोत्साहन और बहुत कुछ उत्पन्न कर सकती है। जैसा कि अक्सर कहा जाता है, संतोष और आत्मसंतुष्टि एक समान नहीं है। हम सभी को खुद को संतुष्ट रहने, कृतज्ञता में तैरने और वर्तमान को मौलिक रूप से स्वीकार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया कभी भी खुश नहीं होने वाली है।

याद रखें, चाहे आप एक उच्च-शक्ति वाले कार्यकारी हों, एक शिक्षक हों, एक रचनात्मक कलाकार हों, एक स्वास्थ्य सेवा कर्मी हों, एक ग्राहक सेवा प्रतिनिधि हों या कोई अन्य कर्मचारी हों, ब्रेक लेने के लाभ सार्वभौमिक हैं और आपकी उत्पादकता, मानसिक स्वास्थ्य और समग्र नौकरी की संतुष्टि को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। इसलिए अपने काम के घंटों के बीच में कुछ विश्राम लेने की पूरी अनुमति देने का प्रयास करें।

आप की बात

ईवीएम पर फिर विवाद

राहुल गांधी ने ईवीएम पर बयान दिया है कि भारत में ईवीएम मशीन एक ब्लैक बॉक्स की तरह है जिसकी जांच की किसी को भी अनुमति नहीं रहती है। अखिलेश यादव ने अगला चुनाव मत पत्र से कराने की वकालत की है। यह सारा विवाद एलन मस्क के ईवीएम पर बयान से शुरू हुआ है। उन्होंने कहा है कि ईवीएम हैक हो सकती है अत: चुनाव में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमारे देश में चुनाव आयोग सहित सुप्रीम कोर्ट भी ईवीएम मशीन पर किसी भी विवाद को नकार चुके हैं। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का कहना है कि भारतीय ईवीएम सुरक्षित है और मस्क का बयान अमेरिका में प्रयोग होने वाली ईवीएम पर केन्द्रित है। लेकिन इसके बाद फिर मस्क ने अपनी बात दुहराई है। सवाल है कि यदि ईवीएम को हैक किया जा सकता है या किया गया होता तो भाजपा को पूर्ण बहुमत से वंचित क्यों होना पड़ता तथा कांग्रेस की सीटें लगभग दूनी क्यों हो जातीं। मस्क जैसे तकनीकविद का ज्ञान अपनी जगह, पर इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वे अपनी टेस्ला कंपनी को अपनी शर्तों पर भारत लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं और मोदी इस दबाव के समक्ष झुकने को तैयार नहीं हैं। विपक्ष नाकामियां छिपाने के लिए ईवीएम पर सवाल उठाता रहेगा, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा।

– **मनमोहन राजावत,** शाजापुर

एनसीईआरटी पाठ्यक्रम

स्कूली पाठ्यक्रम के भगवाकरण आरोपों को एनसीईआरटी के डायरेक्टर ने खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि स्कूली पाठ्य पुस्तकों में गुजरात दंगों और बाबरी मस्जिद गिराए जाने के संदर्भों को इसलिए संशोधित किया गया क्योंकि दंगों के बारे में पढ़ाना हिंसक और अवसादग्रस्त नागरिक पैदा कर सकता है। एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी ने कहा कि पाठ्यपुस्तकों में बदलाव वार्षिक संशोधन का हिस्सा है और इसे शोर-शराबे का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। एनसीईआरटी द्वारा पुस्तकों में संशोधन किया जाना समयोचित है। अभी भी हमारी इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में कई तरह की मिथ्या और अनावश्यक जानकारियां भरी पड़ी है। इनमें भी सुधार करके देश के लिए जान लुटाने वाले वीर योद्धाओं के शौर्य का उचित वर्णन किया जाना चाहिए। पाठ्यपुस्तकों व खासकर इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में बदलाव विवाद का विषय बनता है। विडंबना है कि यह विवाद राजनीतिक दृष्टिकोण से पैदा होता है। ऐसे में शिक्षकों के बीच एक सर्वानुमति विकसित करने का प्रयास होना चाहिए कि भारत का इतिहास तटस्थ दृष्टिकोण से क्या है? और इसे छात्रों की पुस्तकों में किस सीमा तक समाहित होना चाहिए?

– **सुभाष बुडावन वाला,** रतलाम

विश्व शांति को खतरा

स्विटजरलैंड में शांति सम्मेलन भी रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने का कोई रास्ता नहीं खोज पाया और बिना किसी समाधान के खत्म हो गया। संयुक्त बयान पर भारत ने हस्ताक्षर न कर अपनी गुटनिरपेक्ष नीति दर्शायी है। रूस-यूक्रेन युद्ध को दो वर्ष होने वाले हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि युद्ध इतना लंबा खिंचेगा और यूक्रेन रूस जैसी महाशक्ति के सामने इतने समय तक टिक पाएगा। वास्तव में यूक्रेन के पास इतनी क्षमता थी भी नहीं। मगर अमेरिका और नाटो देशों द्वारा हथियार व आर्थिक सहायता से यह युद्ध विकराल होता जा रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ सहित सभी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं कोशिश कर कर के हार गई है। उधर इसराइल हमास युद्ध भी जारी है इन युद्धों से यह तय हो गया है कि परमाणु संपन्न राष्ट्र कभी.भी पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। चीन भी पर्दे के पीछे से रूस को गुप्त रूप से हथियारों की सप्लाई कर रहा है। चीन ने हाल ही मैं अपने परमाणु बमों की संख्या मैं और इजाफा कर लिया है। युद्ध यदि ऐसे ही चलते रहे तो विश्व के निर्दोष नागरिक इसका सर्वाधिक खामियाजा भुगतते रहेंगे। इन युद्धों से विश्व शांति को खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में एक नए प्रकार का शीतयुद्ध पैदा होने की आशंका भी राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं।

– **विभूति बुपक्या,** खाचरोद

कृषि व वाणिज्य का महत्व

एक प्राचीन कहावत के अनुसार पहले सबसे श्रेष्ठ कार्य कृषि को समझा जाता था। दूसरे नंबर पर वाणिज्य एवं व्यापार तथा सबसे अंत में चाकरी अर्थात नौकरी आती था। लेकिन अब नौकरी को सर्वश्रेष्ठ मान लिया गया है। हमारे किसान भाई जमीनें बेच रहे हैं, खेती योग्य जमीन का रकबा कम होता जा रहा है और गांवों से शहरों की ओर पलायन बढ़ रहा है। किसानों के बेटे यथासंभव परंपरागत कृषि कार्य छोड़कर नौकरी करने लगे हैं। कई परंपरागत व्यवसायियों के बेटे अपने व्यवसायों से मुंह मोड़ कर नौकरियों की ओर उन्मुख हो रहे हैं। सरकारी व निजी क्षेत्र में नौकरियों के बढ़ते आकर्षण के कारण तलाश कर कृषि व वाणिज्य को पुराना महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के प्रयास करने चाहिए। देश का अन्नदाता और व्यवसायी ही जब अपने परंपरागत कार्य से मुंह मोड़ने लगेगा तो देर सबेर हमारे देश में विषम परिस्थितियों का निर्माण होने में देर नहीं लगेगी। वैसे भी एआई जैसी नई तकनीकों के व्यापक होने के बाद अनेक प्रकार की नौकरियां समाप्त हो जाएंगी। ऐसे में लगता है कि पुरानी कहावत एक बार फिर बदलते समय में सही हो जाएगी।

–**ललित महालकरी,** इंदौर

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से responsemail.hindipioneer@gmail.com पर भी भेज सकते हैं।